A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 06 मार्च, 2025

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 148, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग से वंशवादी लोकतंत्र मजबूत होगा?

कमलेश पांडे

वंशवादी लोकतंत्र का क्रांतिकारी भूमि बिहार में अपनी गहरी जड़ें जमाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है! यह लोकतंत्र की जननी वैशाली की मूल भावनाओं को मुंह चिढ़ाने जैसा है। ऐसा इसलिए कि सूबाई राजनीति को विगत 4 दशकों तक प्रभावित करते रहने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, जदयू के मुखिया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार और लोजपा आलाकमान रहे स्व. रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने अपने-अपने लाड़ले क्रमशः तेजस्वी यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री बिहार, चिराग पासवान, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार और निशांत कुमार, सीएम इन वेटिंग, बिहार को अपनी राजनीतिक विरासत (सियासी जमींदारी) सौंप चुके हैं!

इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही देरी से फैसला किया हो, लेकिन 'देर आयद दुरुस्त आयद' की भांति वो निशांत कुमार के लिए अपने समर्थकों से मजबूत फील्डिंग भी करवा रहे हैं। इससे प्रदेश की राजनीति में कई सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए इन क्षेत्रीय राजनीतिक सूबेदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की राह पर भाजपा का चलना देश की वैचारिक राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जबकि भाजपा को इतनी ऊंचाई देने वाली टीम का मानना है कि चूंकि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के लिए वो लोग जैसे को तैसा वाली राजनीति देंगे।

भाजपा की इसी सोच का फायदा उठाते हुए उसके दो बड़े कद्दावर नेताओं यानी पार्टी में नम्बर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार और नम्बर 3 की हैसियत पर जा चुके राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार भी अपने पुत्रों क्रमशः जय शाह और पंकज सिंह-नीरज सिंह को महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचा चुके हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि जब नौकरशाह का बेटा नौकरशाह, न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश, उद्यमी का बेटा उद्यमी बन सकता है तो किसी राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता है! बात में तो दम है, लेकिन भारतीय संविधान भी इस विषय में मौन है! इससे साफ है कि सत्ता की एक अलग सोच होती है जो राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाही में भी लगभग एक समान होती है। यह सोच है वंशवादी सोच, जहां राजा या नेता खुद को महफूज समझता है।

यदि आप आजादी के आंदोलनों, संपूर्ण क्रांति और अन्ना हजारे के आंदोलनों पर गौर करेंगे तो यह साफ पता चलेगा कि इन सबका कुछ अघोषित एजेंडा रहा है, जिसमें व्यक्तिवाद, सम्पर्कवाद और वंशवाद सर्वोपरि है। हैरत की बात तो यह है कि जो समाजवादी-राष्ट्रवादी 1970-80-90 के दशक तक नेहरू-गांधी परिवार के वंशवाद का विरोध कर रहे थे, और 'तख्त बदल दो ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो' जैसे नारे लगा रहे थे, उन्होंने कैसा क्षेत्रीय वंशवाद चलाया, अब जगजाहिर हो चुका है। हालांकि, इनमें सबसे धैर्यशाली निकले बिहार के कद्दावर मुख्यमंत्री और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने भी जब अपने बेटे निशांत कुमार को सियासत में उतारने की हरी झंडी दे दी और उनके संग गुलदस्ता वाली फोटो वायरल करवा दिया, तो लोगों के दिलोदिमाग में इस वंशवादी लोकतंत्र को लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं।

पहला सवाल यह कि क्या पारिवारिक लोकतंत्र से आम भारतीयों का भला हो पाएगा? दूसरा सवाल यह कि, जो लोग हर बात में ब्राह्मणों या सवर्णों को कोस रहे थे, उन्होंने सत्ताधीश बनने के बाद कैसा आचरण प्रस्तुत किया? तीसरा सवाल यह कि, वंशवादी नेताओं ने अकूत सम्पत्ति जमा करते हुए हमारे देश की राष्ट्रीय सम्पदाओं को निजी हाथों में सौंपते जा रहे हैं और कोई राजनीतिक चहलकदमी नहीं दिखाई-सुनाई पड़ रही है, क्या इससे आम आदमी का भला होगा? चौथा सवाल यह है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता का हश्र आने वाले दिनों में क्या होगा।

यह सवाल इसलिए कि जब तपे-तपाए नेताओं की जगह उनके अनुभवहीन पुत्र ले लेते हैं तो सिस्टम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, जैसा कि उससे उम्मीद किसी भी सभ्य समाज को होती है। इससे पार्टी और नेता, दोनों कमजोर होते हैं। भारत और भारतीय जनमानस इसी संक्रमण कालीन स्थिति से गुजर रहे हैं।

ऐसे में बिहार में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुनि चौधरी के पुत्र और मौजूदा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (कुशवाहा जाति) की सियासी धार को कुंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार (कुर्मी जाति) की जो सियासी लॉन्चिंग हो रही है, उससे लवकुश समाज की राजनीति कितनी मजबूत होगी, यह तो वक्त बताएगा।लेकिन जब उम्र गत कारणों से नीतीश कुमार राजनीति से अवकाश लेने के मुहाने पर खड़े हैं, तब उन्होंने अपने पुत्र की सियासी लॉन्चिंग कराकर यह संदेश दिया है कि भाजपा और कांग्रेस चाहे जो मंसूबे पाले, लेकिन बिहार की भावी राजनीति तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, चिराग पासवान के ही इर्द-गिर्द घूमेगी।

यही वजह है कि बिहार में निशांत कुमार की शानदार लॉन्चिंग का गुप्त ठेका तेजस्वी यादव ने ले लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार ने अपना मन बना लिया है। इसलिए बीजेपी यहां सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में मौजूद संघी तत्व उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। वहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बेशक, अगर निशांत कुमार आगे आते हैं तो जदयू पार्टी को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसलिए जदयू में मौजूद संघियों की मदद से बीजेपी में कई लोग उनके प्रवेश को रोकने की साजिश में लगे हुए हैं। दरअसल, बिहार में निशांत कुमार की शानदार लॉन्चिंग का गुप्त ठेका तेजस्वी यादव ने सिर्फ इसलिए ले लिया है कि उन्हें पता है कि जबतक जदयू है, तभी तक राजद की सत्ता में वापसी की संभावना है। और यदि भाजपा, जदयू के गैप को भर देगी तो राजद भी कभी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाएगा, पड़ोसी यूपी वाली सपा की तरह। हालांकि, स्वभाव से सुस्त निशांत कुमार अपने पिताश्री नीतीश कुमार की उम्मीदों पर कितने खरे होंगे, यह तो बिहार विधानसभा चुनाव जनादेश 2025 से ही पता चलेगा। क्योंकि सियासी सफलता के लिए जिस राजनीतिक चतुराई की जरूरत होती है, वह तो उनमें कभी दिखी नहीं।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

जीआईएस भोपाल से ग्लोबल हुआ प्रदेश का स्टार्ट-अप इको सिस्टम

सीएम बोले-मध्यप्रदेश भी तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जीआईएस-भोपाल में देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न पर काम करते हुए मध्यप्रदेश भी तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्ट-अप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रयास मध्यप्रदेश को 'स्टार्ट-अप और नवाचार का केंद्र' बनाना है, जहां युवा उद्यमियों के आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले। जीआईएस-भोपाल में आयोजित 'फ्यूचर-फ्रंटियरः स्टार्ट-अप पिचिंग' सेशन नें प्रदेश के स्टार्ट-अप्स इकोसिस्टम को पंख दे कर ग्लोबल बना दिया है। आधुनिक तकनीक के इस युग में देश के स्टार्ट-अप जगत में मध्यप्रदेश बहुत तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज चुका है। जीआईएस-भोपाल में 20 से अधिक यूनिकॉर्न के संस्थापकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। स्टार्ट-अप पर फोकस्ड सेशन 'फ्यूचर-फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग' में शामिल होने के लिए कुल 180 स्टार्ट-अप्स ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 25 हाईली पोटेंशियल स्टार्ट-अप्स ने प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों के विश्लेषण के बाद उन्हें जरूरी मार्गदर्शन और निवेश के अवसर भी मिले। इस सेशन में कुल 47 स्टार्ट-अप शामिल हुए थे। इनमें से 19 स्टार्ट-अप्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए।

स्टार्ट-अप को मिल रही है वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों के स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 18 फीसदी, अधिकतम 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल रही है। अन्य स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 15 प्रतिशत सहायता, अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ इन्क्यूबेटर विस्तार के लिए 5 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान, स्टार्ट-अप्स के ऑफिस किराए में 50 फीसदी राशि की वापसी (तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये) की भी व्यवस्था की गई है। नीति में पेटेंट कराने पर 5 लाख रुपये तक की सहायता और पेटेंट फाइल करने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

महिला उद्यमियों के स्टार्ट-अप को विशेष प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश में इस समय 4,900 से अधिक स्टार्ट-अप संचालित हो रहे हैं। इनमें से करीब 44 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स महिलाओं द्वारा संचालित हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 'स्टार्ट-अप इंडिया' के तहत पंजीकृत स्टार्ट-अप्स की संख्या को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को 200 प्रतिशत तक बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं और उत्पाद-आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की स्टार्ट-अप नीति और क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स को वित्तीय मदद, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता और नीतिगत मदद मुहैया कराई जा रही है।

53 तरह के पेड़ काटने की अनुमति का नोटिफिकेशन रद्द

एचसी की लार्जर बैंच ने कहा-मप्र में पुष्पा स्टाइल में हो रहा काम

भोपाल। जैसे पुष्पा फिल्म में तस्कर, विधायक और अधिकारी सिंडिकेट चलाते हैं ठीक उसी तरह की स्थिति मध्यप्रदेश में भी है। ये तल्ख टिप्पणी की है एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली लार्जर बैंच ने। 53 तरह के पेड़ों की कटाई को अनुमति देने वाले सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ 2019 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सहित हाईकोर्ट के 3 जजों की लार्जर बैंच ने मध्यप्रदेश में जंगलों की अवैध कटाई को लेकर सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया।

हाईकोर्ट ने 24 सितंबर 2019 को जारी वो नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार ने 53 तरह के पेड़ों की कटाई और उनकी लकड़ियों के परिवहन को सरकारी अनुमति से छूट दे दी थी। मामले पर कोर्ट ने 100 पन्नों का फैसला सुनाया। बता दें कि इंदौर निवासी विवेक कुमार शर्मा ने 2019 में इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले पर 9 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए फैसला रिजर्व रखा लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साल 2019 में इंदौर के सीसीएफ द्वारा पीसीसीएफ को लिखे गए पत्र का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि 53 तरह के पेड़ों को कटाई की छूट देने से जंगलों में तेजी से कटाई हो रही है, जो वन भूमि को बंजर कर देगी।

सुप्रभात

टहनियों पर लगे पीले पत्ते मत तोड़ो तुम
चन्द रोज़ में खुद बा खुद झड़ जाएंगे,,
बैठा करो कुछ देर तो घर के बुजुर्गों के पास,
एक दिन खुद ही ये आपके पास से चले जाएंगे,,
खर्चनें दो उन्हें बेहिसाब हर चीज़ तुम यारों,
एक दिन सबकुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे,
मत टोको उनको बार-बार उन्हें बात दोहराने पर,
एकदिन खुद हमेशा के लिए ख़ामोश हो जाएंगे,,
इनका आशीर्वाद ले लिया करो सर पर हाथ
रखकर,
वर्ना फिर ये तस्वीरों मे ही नज़र आएंगे,
दो वक्त की रोटी तो समय पर दे दिया करो,
इज्ज़त और प्यार मोहब्बत के साथ,,
वर्ना फिर श्राद्ध मे भी देखना खाने नही आएंगे,,
आँखे इन्तज़ार करेंगी इन बूढ़ी आत्माओं का
पर ये कहीं नज़र नहीं आएंगे,,
एक दिन कीमत खुद जान जाओगे उनकी
जब उनकी उम्र पर तुम आओगे,,,

मुक्ता त्रिपाठी

माधव नेशनल पार्क होगा प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र

सीएम बोले-वन्यजीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा चंबल

मुख्यमंत्री यादव शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे बाघों का जोड़ा

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत में टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके मध्यप्रदेश को जल्द ही एक नए टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात मिलने जा रही है। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क प्रदेश का 9वां बाघ संरक्षित क्षेत्र होगा, जो चंबल क्षेत्र में वन्य जीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं बाघों का एक जोड़ा माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे।

चंबल रेंज में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। एशिया में पहली बार चीते भी चंबल के कूनो नेशनल पार्क में दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियाल एवं डॉल्फिन प्रोजेक्ट पर भी कार्य चल रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मीडिया को जारी संदेश में कहा कि देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्यप्रदेश में हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मध्यप्रदेश आते हैं।

बाघ संरक्षित क्षेत्र में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए सभी नेशनल पार्कों में सीजन भर पर्यटकों का आवागमन रहता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण से प्राप्त उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी।

मांडना से सजा विक्रमादित्य शोधपीठ का आंगन

उज्जैन में विक्रमोत्सव

उज्जैन से डॉ. जफ़र महमूद

विक्रमोत्सव के 125 दिवस के कार्यक्रमों की श्रृंखला में साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों की खुशबू से उज्जैन नगर पूरी तरह महकता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरी श्रृंखला को लोक से जोड़ने की सफल कोशिश की है। किसी के तहत धरातल के विभिन्न भू-भागों पर प्रकृति की विविधताओं के अनुसार लोक परंपराएँ भी एक दूजे से विविधता लिए हुए हैं। इन सभी सांस्कृतिक धरोहरों में मध्यप्रदेश के मालवांचल का मांडना अपनी विशिष्ट आकृतियों और प्राकृतिक रंगों के माध्यम से मालवा के घरों पर अपनी छाप छोड़ता आ रहा है। नवरात्र, दिवाली सहित सभी मांगलिक उत्सवों पर पगल्या, सातिया (स्वस्तिक), वृक्ष, हल, आदि सांस्कृतिक प्रतीकों से मालवा के घरों को सजाया जाता है। इस अद्वितीय कला को संरक्षित करने व इसके सांस्कृतिक महत्व को नवान्कुरों में रौपने का कार्य विक्रमोत्सव अंतर्गत आयोजित मांडना कला कार्यशाला के माध्यम से किया जा रहा है। इस कला के प्रति स्वयं को समर्पित करने वाली श्रीमती कृष्णा वर्मा इस कार्यशाला का संयोजन कर रही है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के कार्यालय में 8 मार्च तक आयोजित इस कार्यशाला में स्थानीय कलाकार, छात्र-छात्राएँ भाग ले रहे है। बिड़ला भवन की दीवारों पर इस कला को देखा जा सकता है। शिविर में नन्दिनी प्रजापति, पंकज

सहरा, प्रथा शाक्य, लक्ष्मी कुशवाह, आदित्य चौहान, रिदिमा सोनी, एनी मोदी, ईशा सोनगरा, जीत डे, राजु पुष्पद, अलका कुमारी, प्रिंस परमार, नेसा ख़ान, सलोनी परमार, बबीता व सिद्धार्थ आदि लोक कला प्रेमी व विद्यार्थी शामिल हुए।

अयोध्या के राम मंदिर की संगीतमय गाथा

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य, उनके युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव के अंतर्गत उज्जयिनी नृत्य नाट्य समारोह का शुभारम्भ हुआ। इस मौके पर मोहित शेवानी एवं दल द्वारा अयोध्या के राम मंदिर की संगीतमय गाथा को प्रस्तुत किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाह, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज, पुराविद डॉ. रमण सोलंकी, कवि दिनेश दिग्गज ने गुलदस्ता भेंट कर कलाकारों का स्वागत किया। भारतीय जनमानस की आस्था में भगवान श्रीराम सर्वोपरि है। महाकाव्य रामायण और उसकी गाथाएँ इस देश के घर-घर में पढ़ी और गायी जाती है। राम की गाथा हर काल में अनेक ढंग और रूप में उल्लेखित होती रही है। प्रस्तुति में राम मंदिर की संघर्ष की कहानी जिसमें बलिदान, त्याग, तपस्या, धैर्य और अदम्य साहस की महागाथा को प्रदर्शित किया गया है। एक घंटे तीस मिनट की इस संगीतमय महागाथा में श्रीराम मंदिर संघर्ष के नायकों और नायिकाओं के किस्सों के साथ श्रीराम मंदिर के इतिहास को रेखांकित किया गया है। प्रस्तुति के दौरान कई वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया। समय-समय पर दोहों, चौपाइयों, भजनों और गीतों की प्रस्तुति भी होती है। मंच पर कहानीकार मोहित शेवानी, रचनाकार प्रबुद्ध सौरभ, गायक शुभम नथानी, अभिषेक बिरथरे तथा गायिका श्रेया एवं श्रीजा उपाध्याय ने अपनी प्रस्तुति से समां बांध दिया। संचालन डॉ. वैशाली शुक्ला ने किया।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22°c न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार,06 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

अच्छी खबर | 2 शहरों के बीच चलेगी हाइपरलूप ट्रेन, मिल गई मंजूरी

4 घंटे की यात्रा सिर्फ 25 मिनट में, टेस्टिंग ट्रैक तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में पहली हाइपरलूप परियोजना मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित है। मौजूदा समय में यह दूरी 3-4 घंटे में तय होती है, जबकि हाइपरलूप के जरिए यह सफर मात्र 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। रिपोर्ट मुताबिक, इसमें एक पॉड में 24 से 28 यात्री बैठ सकते हैं। हार्डट हाइपरलूप को पहला सफल परीक्षण 2019 में हुआ। हाइपरलूप एक हाई-स्पीड ट्रेन है, जो ट्यूब में वैक्यूम में चलती है। इसकी अधिकतम गति एक हजार किलोमीटर प्रतिघंटे तक जा सकती है। इसमें पॉड्स को वैक्यूम ट्यूब के भीतर चुंबकीय तकनीक पर चलाया जाता है। इस प्रणाली में ऊर्जा खपत बेहद कम होती है और यह लगभग शून्य प्रदूषण उत्पन्न करती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को एक्स पर वीडियो साझा कर कहा कि हाइपरलूप यात्रा के साधनों में आधुनिक बदलावों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमने आईआईटी मद्रास को दो बार एक-एक मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया है। इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक मिलियन डॉलर का तीसरा अनुदान देने का समय आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस हाइपरलूप के शुरू होने से महज 30 मिनट में 300 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकेगा। स्पेनिश कंपनी जेलरॉस हाइपरलूप प्रणाली विकसित कर रही है। इसका लक्ष्य यूरोपीय शहरों को 1000 किमी/घंटा की स्पीड से जोड़ना। बेंगलुरु-चेन्नई के बीच हाइपरलूप ट्रेन चलाने की योजना पर रेलवे काम कर रहा है। रेलवे मंत्रालय और आईआईटी मद्रास इस तकनीक पर शोध कर रहे हैं। यह दूरी महज 30 से 40 मिनट में तय हो सकेगी। चीन एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन हाइपरलूप आधारित मैग्लेव ट्रेन विकसित कर रहा है।

सावरकर वाले बयान पर फंसे राहुल, 200 रुपए का जुर्माना

लखनऊ कोर्ट का आदेश, 14 अप्रैल को पेश हों कांग्रेस नेता

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा- यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे।

एमआईएल पर हाई कोर्ट का आदेश सुरक्षित

मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बोरीवली और ठाणे के बीच ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण का ठेका कंट्रक्शन कंपनी एमईआईएल को देने के लिए एमएमआरडीए के खिलाफ दायर जनहित याचिका सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की युगल पीठ ने पीआईएल पर सुनवाई की। गौरतलब है कि हैदराबाद के रवि प्रकाश ने पीआईएल दायर कर रही आरोप लगाया कि एमईआईएल द्वारा प्रस्तुत यूरो एक्जिम बैंक की बैंक गारंटी वैध नहीं हैं। पीआईएल में इसकी जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान एमएमआरडी की ओर से भारतीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यूरो एक्जिम बैंक द्वारा जारी की गई गारंटियां भारतीय स्टेट बैंक और महाराष्ट्र स्टेट बैंक द्वारा प्रमाणित हैं और इसकी जानकारी होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता ने पीआईएल दायर की। एमईआईएल की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता खंबाटा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अदालत की अवमानना की है और जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया है। यह व्यक्तिगत द्वेष से दायर की गई है।

देश में जल्द खत्म होगा 'सरपंच पतियों' का राज

महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की खास पहल

नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने और उनके निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' के तहत मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में 1,200 से अधिक महिला पंचायत नेताओं की उपस्थिति में इस पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण प्राइमर भी जारी किया गया, जिसमें महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस अभियान का उद्देश्य 'सरपंच पति' जैसी प्रथा पर अंकुश लगाना है।

नेताओं ने दिया 'प्रॉक्सी नेतृत्व' पर कड़ा संदेश- विज्ञान भवन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सरपंच पति, मुखिया पति और प्रधान पति के नाम पर महिलाओं की भूमिका को छीनने की कड़ी आलोचना की। वहीं, युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे ने महिलाओं से आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने का आह्वान किया।

● **महिला नेताओं को कानूनी जानकारी से सशक्त बनाने पर जोर-** अभियान के तहत जारी प्राइमर महिला प्रतिनिधियों को कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, बाल शोषण, बाल विवाह, लिंग आधारित भ्रूण हत्या, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, छवि आधारित दुर्व्यवहार, पहचान की चोरी और हैकिंग जैसे डिजिटल अपराधों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह पहल पंचायत स्तर पर महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को न केवल कानूनी सशक्तिकरण मिलेगा, बल्कि वे अपने गांवों में लैंगिक समानता और महिला अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

हिंदुओं का जीता भरोसा, अब केरल में होगा 'खेला'

भाजपा बिगाड़ सकती है लेफ्ट-कांग्रेस का चुनावी गणित

तिरुअनंतपुरम (एजेंसी)। केरल विधानसभा चुनाव में अभी एक वर्ष बाकी है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट की अगुवाई वाले एलडीएफ ने चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। दोनों गठबंधन जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के साथ चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहना रहे हैं। इनके बीच मतदाताओं में पैठ बना रही भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व वाम दलों की चुनौतियां बढ़ा सकती है। केरल में पिछले दस वर्षों से वाम दल सत्ता में है। हालांकि वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह कहना मुश्किल है कि लोकसभा का असर विधानसभा में दिखाई देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने सरकार बनाई थी। नायर और मछुआरा समुदायों पर भाजपा की नजर चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि पहले मतदाताओं के सामने यूडीएफ और एलडीएफ दो ही विकल्प थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता दोनों गठबंधनों के वोट बैंक में सेंध लगाते हुए भाजपा अपनी जगह बना रही है। नायर और मछुआरा समुदायों पर भाजपा की नजर है। दोनों समुदाय अमूमन चुनाव में एलडीएफ का समर्थन करते रहे हैं। भाजपा के प्रवेश से सियासत बदली केरल में राजनीति दो ध्रुवीय रही है, लेकिन भाजपा के प्रवेश के बाद सियासत बदल गई है। अगर भाजपा सभी सीट पर चुनाव लड़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अभी अपना प्रदर्शन बरकरार रखती है तो यह यूडीएफ और एलडीएफ दोनों का गणित बिगाड़ सकती है।

सरकारी आवासों की मरम्मत पर 5 लाख खर्च कर सकेंगे सांसद

लोकसभा की हाउस कमेटी ने खर्च में की 230 फीसदी की बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सांसद अपने सरकारी आवासों में बदलाव या मरम्मत के लिए अब अधिक धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। लोकसभा की हाउस कमेटी ने इसके लिए मिलने वाली राशि की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है, जो 230 फीसदी की बढ़ोतरी है। यह निर्णय सांसदों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि कई सांसद अपने आवासों में ऑफिस, गेस्ट रूम या अन्य आवश्यक सुविधाएं जोड़ना चाहते हैं। नॉर्थ और साउथ एवेन्यू में स्थित सांसदों के बंगले और फ्लैट काफी पुराने हैं जिसके चलते मरम्मत और बदलाव की लागत बढ़ रही थी। लोकसभा सचिवालय के एक सर्कुलर में कहा गया, सांसदों के आवास में अतिरिक्त निर्माण/संशोधन के लिए वित्तीय सीमा 5,00,000 रुपये कर दी गई है।

किसानों की चंडीगढ़ में नो-एंट्री, सीमाएं सील

स्टेट और नेशनल हाईवेज पर ही बैरिकेडिंग

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के 37 किसान संगठनों से जुड़े लोग आज चंडीगढ़ में धरना देने पहुंचने वाले थे। इन किसानों ने मंगलवार शाम को ही अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया था, लेकिन पंजाब प्रशासन की सख्ती के चलते ये लोग चंडीगढ़ नहीं पहुंच पा रहे हैं। संगरूर में ही शाम को पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया था। इसके अलावा होशियारपुर, अबोहर, आनंदपुर साहिब, अमृतसर समेत कई और जिलों में भी ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा चंडीगढ़ की सीमाओं पर पुलिस का सख्त पहरा और बैरिकेडिंग है। इसके चलते किसानों के लिए चंडीगढ़ के अंदर जाना ही मुश्किल हो गया है। उन्हें बॉर्डर से ही लौटाया जा रहा है। किसानों की रणनीति थी कि चंडीगढ़ में एक सप्ताह का धरना दिया जाए, लेकिन उनका पहुंचना ही मुश्किल लग रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसानों को रोकने के लिए सभी स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। चंडीगढ़ सीमा को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। समराला-चंडीगढ़ रोड पर बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लिया गया है। काफी किसानों को वापस लौटा दिया गया है।

मायावती के भाई भी नहीं रहेंगे नेशनल कॉर्डिनेटर

भतीजे आकाश को बाहर करने के बाद लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पार्टी के नेशनल कॉर्डिनेटर नहीं रहेंगे। उन्हें इसी सप्ताह यह जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मायावती ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब वह सिर्फ उपाध्यक्ष के पद पर काम करेंगे। मायावती ने कहा कि आनंद कुमार ने ही एक पद पर ही काम करने की इच्छा जाहिर की, जिसका स्वागत है। मायावती ने एक्स पर लिखा, काफी लम्बे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनन्द कुमार को अभी हाल ही में नेशनल कोआर्डिनेटर भी बनाया गया था। उन्होंने पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है।

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे को मंजूरी

● **केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 6,811 करोड़ रुपए होंगे खर्च**

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने बुधवार को चार धाम यात्रा पर बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर तक जबकि गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर तक रोपवे निर्माण की परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दोनों ही परियोजनाओं पर कुल 6,811 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अकेले सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे परियोजना पर 4,081.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण की समय सीमा 4 से 6 साल है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के निर्णयों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण डीबीएफओटी मोड पर किया जाएगा। रोपवे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना है। यह रोपवे सबसे उन्नत ट्राई-केबल डिटैचेबल गोंडोला (3एस) तकनीक पर आधारित होगा।

एक बार फिर निकलेगा बोफोर्स घोटाले का जिन्न

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने अमेरिका को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की मांगी गई है। भारत सरकार के इस नए कदम से स्वीडन से 155 मिमी फील्ड आर्टिलरी गन्स की खरीद को लेकर राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के तहत हुए इस घोटाले की जांच को फिर से शुरू करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि सीबीआई ने हाल ही में एक विशेष अदालत द्वारा जारी पत्र अमेरिकी न्याय विभाग को भेजा। इस पत्र में एजेंसी ने अमेरिकी निजी जासूसी कंपनी फेयरफैक्स के प्रमुख माइकल हर्शमैन से जुड़ी जानकारी की मांग की है। 2017 में हर्शमैन ने दावा किया था कि तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुस्से में थे जब उन्होंने स्विस बैंक खाते मॉन्ट ब्लांक का पता लगाया, जहां बोफोर्स से रिश्वत की रकम कथित रूप से जमा की गई थी।

परिसीमन विवाद | पीएम मोदी को दिया अटल वाला फॉर्मूला, पेश किया प्रस्ताव

सीटें घटने का डर दिखा स्टालिन ने जुटाए 35 दल

चेन्नई (एजेंसी)। लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर बुधवार को तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में 35 दलों की मीटिंग हुई। इस बैठक में स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी ने एकमत से सहमति जताई। इस प्रस्ताव में पीएम मोदी से मांग की गई है कि परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना के अनुपात को ही आधार माना जाए। उसके आधार पर ही लोकसभा सीटें तय हों और यह सीमा अगले 30 सालों के लिए बरकरार रखी जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि दक्षिण भारत के अलावा अन्य राज्यों को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस मीटिंग में मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद रहे। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए और यह तय किया जाए कि यदि सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसका अनुपात वर्तमान जैसा ही हो। उनकी स्पष्ट मांग थी कि यदि नई जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन हुआ और सीटें बढ़ती हैं तो फिर उसका अनुपात वही रहे, जो फिलहाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उनकी सीटें कम हो और उनकी राजनीतिक ताकत भी घट जाए। उनकी बैठक में भाजपा के अलावा 4 अन्य छोटे दलों के नेता नहीं पहुंचे। भाजपा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और उससे ध्यान हटाने के लिए एमके स्टालिन परिसीमन वाला कार्ड खेल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई और होम मिनिस्टर अमित शाह तो दोहरा चुके हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी। सीएम स्टालिन ने एक बार फिर से कहा कि सांसदों की संख्या बढ़ने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी ताकत में कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो लोगों ने फैमिली प्लानिंग की है। इसके बाद हमें उसकी सजा मिले तो यह अन्याय ही है। प्रस्ताव में कहा गया, 'सभी राज्यों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में भरोसा दिया था कि 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही परिसीमन किया जाए। अब पीएम मोदी को भी ऐसा भरोसा देना चाहिए कि 2026 से अगले 30 सालों तक लोकसभा सीटों के परिसीमन का यही पैमाना बना रहेगा।'

चौराहे पर मंत्री की फोटो के नीचे जुबान लटकाई

जनता को भिखारी कहने वाले बयान का विरोध, इंदौर कांग्रेस ने पटेल को अहंकारी बताया

इंदौर। मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान वाले मामले में इंदौर में कांग्रेस नेता ने फोटो पर उनकी जुबान बनाकर रीगल चौराहे पर लगा दी। जिस पर उन्होंने लिखा है वोट लेने से पहले जनता भगवान। वोट लेने के बाद जनता भिखारी। पोस्टर को देखकर यहां से गुजरने वाले भी आश्चर्य में पड़ गए। जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने पोस्टर रीगल चौराहे पर लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने जिस तरह मध्यप्रदेश की सात करोड़ जनता को भिखारी बताया है वह काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रह्लाद पटेल का यह कहना है कि मध्यप्रदेश की

जनता अपनी समस्याओं अपनी मांगों को लेकर भिखारी की तरह हर कार्यक्रम में आ जाती है। जिस तरह का उनका बयान है उससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मध्यप्रदेश की 7 करोड़ जनता को मतदाताओं को जिस लोकतंत्र में मतदाता भगवान होता है, उसे भिखारी बताकर अपमानित किया जा रहा है।

6 फीट लंबी दो कलर की जुबान लगाई

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री प्रह्लाद पटेल माफी मांगने की जगह यह कह रहे है कि मैंने जो कहा सही कहा यह दर्शाता है कि वे कितने अहंकारी है। सत्ता के नशे में उनकी नजर में जनता भिखारी है। इस बयान के बाद न तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉ.मोहन यादव और न ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी.शर्मा ने कोई कार्रवाई की और न ही केंद्रीय नेतृत्व ने। इसके विरोध में कांग्रेस ने रीगल चौराहे पर मंत्री प्रह्लाद पटेल की दो कलर की 6 फीट लंबी जुबान को लटकाया और एक लाल रंग की ओर एक काले रंग की जुबान जिस पर लिखा गया वोट लेने से पहले जनता भगवान, वोट लेने के बाद जनता भिखारी। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं ने मंत्री प्रह्लाद पटेल के इस्तीफे की मांग की है साथ ही कांग्रेस द्वारा निरंतर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

फर्जी डिप्टी कलेक्टर ने छात्र को ठगा

नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाख रुपए लिया ; लालबत्ती कार से आता था, ताकि रौब जमे

इंदौर। डिप्टी कलेक्टर बनकर महाराष्ट्र के ठग ने इंदौर के एक युवक से 1 लाख से अधिक रुपए ठग लिए। इस मामले में एमआईजी पुलिस ने अरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी संकेत चव्हाण ने मंदिर में मिले बीबीए स्टूडेंट सारांश मिश्रा को स्टेनोग्राफर की नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लिए और फिर कई दिनों तक टालमटोल करता रहा। मामला दो दिन पहले सामने आया था। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की। टीआई सीबी सिंह ने बताया कि सारांश मिश्रा की शिकायत पर संकेत चव्हाण निवासी स्मार्ट लिंविग पुष्प विहार कॉलोनी खजराना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सारांश ने पुलिस को बताया कि आरोपी संकेत से उसकी पहचान जनवरी 2025 में महालक्ष्मी मंदिर में हुई थी। संकेत लालबत्ती कार से मंदिर आया था। बातचीत में उसने खुद को भोपाल में राजस्व डिपार्टमेंट में अपर कलेक्टर के पद पर

पदस्थ होने की बात कही थी।

आरोपी ने 3 लाख रुपए मांगे तब शक हुआ

शिकायतकर्ता सारांश ने बताया कि वह अपने पिता को लेकर संकेत के बताए पते पर रुपए लेकर पहुंचा। घर के बाहर दरवाजे पर डिप्टी कलेक्टर की नेम प्लेट लगी थी। संकेत ने करीब 1 लाख 10 हजार रूपए 3-4 किश्तों में लिए। बाद में संकेत 3 लाख रुपए मांगने लगा। कुछ डॉक्यूमेंट बनवाए, लेकिन जब उसके डिपार्टमेंट में जांच कराई तो वह फर्जी निकला। शंका होने पर उसके घर पहुंचे तो वहां से नेम प्लेट हटी हुई थी। जब जानकारी निकाली तो पता चला कि संकेत नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला है। वहां भी इस तरह की ठगी कर फरार हुआ है। उसके खिलाफ पुलिस में जाने की बात कही तो उसने करीब 40 हजार रुपए दो किश्तों में वापस कर दिए।

कंबोडिया के आईपी एड्रेस से बुना ठगी का जाल

इंदौर के डॉक्टर से 3.8 करोड़ की ठगी में सामने आई महिला की लिंक

इंदौर। इंदौर के एक डॉक्टर के साथ हुई 3.8 करोड़ की ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को कंबोडिया की लिंक मिली है। जिस महिला ने डॉक्टर से बात की थी उसका आईपी एड्रेस कंबोडिया का निकला है। क्राइम ब्रांच टीम इस टेक्निकल एविडेंस पर काम कर रही है। संभावना है कि इसमें कई आरोपी शामिल होंगे। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि डॉक्टर से हुई तीन करोड़ 8 लाख की ठगी के मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। टेक्निकल एविडेंस और आईपी एड्रेस के आधार पर कंबोडिया की लिंक मिली है। डॉक्टर से आरू भट्ट बनकर जिस महिला ने जिस फेक प्रोफाइल से बात की थी वह कहीं न कहीं देश से बाहर की है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। टीमें लगातार इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी है। दूसरे टेक्निकल एविडेंस पर भी काम कर रहे हैं। जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। इस तरह के आर्गेनाइज क्राइम में बड़ी संख्या में अपराधी शामिल होते हैं।

रहवासियों की शिकायत पर खुद जांच करने पहुंचे महापौर

अधिकारियों से कहा- काम की गुणवत्ता सुधारो

इंदौर। एमआईजी कॉलोनी के संजय उद्यान में विकास कार्य चल रहा है। मगर रहवासी यहां के काम से संतुष्ट नहीं थे। इसकी शिकायत लेकर सभी महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पास पहुंचे थे। कुछ दिनों पहले रहवासियों ने शिकायत करते हुए महापौर को बताया था कि वे बगीचे में हो रहे विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है जो काम किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। रहवासियों से शिकायत मिलने के बाद बुधवार को महापौर भार्गव अचानक ही एमआईजी कॉलोनी स्थित संजय उद्यान पहुंच गए। यहां पूर्व क्षेत्रीय पार्षद चंदू राव शिंदे सहित रहवासी संगठन के लोग भी पहुंचे। रहवासियों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत पर महापौर ने खुद पेवर ब्लॉक और सड़क के काम को देखा।

इंदौर में नगर निगम के राजस्व अफसर को धमकी

टैक्स वसूली के लिए पहुंचे थे ; मंगलसिटी सिनेमा के मालिक पर एफआईआर दर्ज

इंदौर। इंदौर में मंगल सिटी सिनेमा के मालिक पर धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

बकाया टैक्स की वसूली पर दी धमकी- जानकारी के अनुसार, नगर निगम अधिकारियों के निर्देश पर सहायक राजस्व अधिकारी महेन्द्र सिंह राठौर (निवासी नंदानगर) बकाया टैक्स वसूलने के लिए मंगल सिटी सिनेमा पहुंचे थे। वसूली टीम ने सिनेमा को 7 दिन का समय दिया और प्रसारण भी बंद करवा दिया था। इसके बाद आंशिक भुगतान किया गया और टीम वापस लौट गई। 1 मार्च की रात सिनेमा मालिक राजेश मंगल ने महेन्द्र सिंह को फोन किया और कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी। इस घटना के बाद महेन्द्र सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और अगले दिन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला- शिकायत की जांच के बाद विजयनगर पुलिस ने मंगल सिटी सिनेमा के मालिक राजेश मंगल के खिलाफ धारा 351(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार को पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई की।

ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी के टेंडर की शिकायत लोकायुक्त से की

अधिकारियों पर कंपनी की मदद का लगाया आरोप, कहा- अपात्र कंपनी को मिला टेंडर

इंदौर। इंदौर के लोक निर्माण विभागमें टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों ने लोकायुक्त संगठन से शिकायत की है। मंगलवार को की गई इस शिकायत में कहा गया है कि अपूर्व इंटरप्राइजेस को एक टेंडर में अपात्र घोषित किया गया, जबकि उसी कार्य के दूसरे टेंडर में पात्र बताकर टेंडर जारी कर दिया गया। ठेकेदारों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने उक्त कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया। शिकायत में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को हटाकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की गई है। मेंटेनेंस कार्यों के लिए टेंडर पर विवाद छिड़ा हालांकि, अपूर्व इंटरप्राइजेस को तकनीकी स्पेसिफिकेशन की कमी के कारण खारिज कर दिया गया और 19 लाख रुपए के इस टेंडर को 31.11 प्रतिशत कम यानी 13.71 लाख रुपए में रूही इंटरप्राइजेस को अलॉट कर दिया गया। ठेकेदारों का आरोप है कि नियमानुसार विभाग को नया टेंडर निकालना चाहिए था, क्योंकि इसमें तीन कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया।

अपात्र कंपनी को टेंडर देने पर की शिकायत- शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में बताया कि, इस टेंडर प्रक्रिया में

अपूर्व इंटरप्राइजेस, मीरा इंटरप्राइजेस और श्री कालिका ट्रेडिंग कंपनी ने हिस्सा लिया था। मीरा इंटरप्राइजेस ने 19.50 लाख के टेंडर को 35.01 प्रतिशत कम, यानी 12.67 लाख रुपए में भरा। श्री कालिका ट्रेडिंग कंपनी ने 46.99 प्रतिशत कम, यानी 10.33 लाख रुपए में बोली लगाई। अपूर्व इंटरप्राइजेस ने 55.55 प्रतिशत कम, यानी 8.67 लाख रुपए में बोली लगाई। सबसे कम बोली अपूर्व इंटरप्राइजेस की होने के कारण विभाग ने उसे टेंडर जारी कर दिया। ठेकेदारों का आरोप है कि पहले जिस कंपनी को पात्र मानकर टेंडर दिया गया, बाद में उसी कंपनी से जुड़ी दूसरी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे अपात्र घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अपात्र घोषित की गई कंपनी की बोली तुलनात्मक रूप से कम थी।

अधिकारियों पर मदद का लगाया आरोपः लोकायुक्त को सौंपी गई शिकायत में ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि अपूर्व इंटरप्राइजेस के मालिक अर्जुन सिंह, निवासी भोपाल को पर्दे के पीछे से कुछ अधिकारी मदद कर रहे हैं।

42 दुकानों का संपत्तिकर बकाया नगर निगम ने सील की

जेलरोड पर कार्रवाई, नोटिस भेजने के बाद भी जमा नहीं की राशि

इंदौर। इंदौर नगर निगम की टीम ने बुधवार को संपत्तिकर जमा नहीं कराने पर जेलरोड पर कार्रवाई की। टीम ने यहां पर 42 दुकानों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों का कहना था कि कई बार नोटिस भेजने के बाद भी दुकान संचालकों द्वारा बकाया संपत्तिकर जमा नहीं किया जा रहा था। जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम टीम ने सिद्धि विधायक मार्केट में 30 दुकानों को सील किया। वहीं लोधी पंथ धर्मशाला में 12 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। जोन 3 के एआरओ अनिल निकम ने बताया कि संपत्तिकर बकाया होने पर अलग-अलग जोनों में कार्रवाई की जा रही है। महापौर और नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर ये कार्रवाइयां की जा रही है। आज सिद्धिविनायक मार्केट में 30 दुकानों को

सील किया गया है। इन पर 3 लाख रुपए संपत्तिकर बकाया है। वहीं लोधी पंथ धर्मशाला में बनी 12 दुकानों को सील किया गया है। इन पर 7 लाख रुपए बकाया है।

नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं की राशि- उन्होंने बताया कि दुकान संचालकों को बार-बार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने राशि जमा नहीं की थी। आखरी सूचना दी गई, मगर राशि जमा नहीं हुई। इसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर आज दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। एआरओ ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों के फोन आए थे, जिन्हें स्पष्ट कहा गया कि वे बकाया राशि जमा करें, सील खोल देंगे। उन्होंने कहा कि 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके बाद 10 मार्च से ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी।

बेसमेंट में निगम की रिमूवल की कार्रवाई- वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में पार्किंग की जगह अतिक्रमण पर भी नगर निगम की रिमूवल की कार्रवाई जारी है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर ट्रैफिक सुगमता को लेकर बेसमेंट में पार्किंग की जगह व्यवसाय कर अतिक्रमण करने पर निगम ने जोन 13 में रिमूवल की कार्रवाई की। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। जितने बेसमेंट जिन्हें चिह्नित किया गया था जहां उनका कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। उन्हें नोटिस देकर सील किया गया था। भवन मालिकों ने शपथ पत्र देकर उन्हें ठीक करने का कहा था।

इंदौर-शारजाह फ्लाइट के समय में होगा बदलाव

3 अप्रैल के बाद इंदौर एयरपोर्ट से 2 घंटे पहले रवाना होगी शारजाह

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर इंटरनेशल एयरपोर्ट से प्रदेश की एकमात्र सीधी इंटरनेशनल शारजाह उड़ान का समय अप्रैल के पहले हफ्ते से बदल जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी इस उड़ान का संचालन अब दो घंटे पहले करेगी। कंपनी ने इसके लिए दूसरे स्लॉट के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसके अनुसार बुकिंग शुरू कर देगी। बता दें कि पहले नया टाइम स्लॉट नहीं मिलने से इस फ्लाइट के संचालन पर बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा था। दरअसल, इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे की मरम्मत का काम होना है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि 1 अप्रैल से एयरपोर्ट रात 10.30 बजे बंद होगा। इसलिए अब एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी उड़ान को दो घंटे पहले संचालित करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा इसका संचालन सप्ताह में चार दिन सोमवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को किया जाता है। अभी यह उड़ान रात 23.55 पर रवाना होकर रात 2.05 बजे

शारजाह पहुंचती है। नए स्लॉट के अनुसार रात 10.25 बजे इंदौर से रवाना होगी। इंदौर एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फ्लाइट का समय 3 अप्रैल के बाद बदलने की संभावना है। एयरलाइन कंपनी ने भी 3 अप्रैल के बाद की बुकिंग लेना बंद कर दी है। जल्द ही कंपनी इस फ्लाइट की बुकिंग नए समय के अनुसार शुरू करेगी।

इंदौर-शारजाह उड़ान अब तक की सबसे सफल उड़ान- इंदौर ट्रैवल एजेंट्स के अनुसार यह उड़ान अब तक की सबसे सफल उड़ान है। यह इंदौर-दुबई से भी ज्यादा सफल रही है। एजेंट्स का कहना है कि इस उड़ान का समय रात का है, जिसमें यात्री को घाटा होता है। उन्हें कुछ घंटे रूकने के लिए होटल का पूरे दिन का किराया चुकाना होता है।

पीथमपुर में 20 घंटे में ठंडी हुई मशीन, देर रात तक हुई सफाई

महू-पीथमपुर। पीथमपुर स्थित रि-सस्टेनेबिलिटी कंपनी (पूर्व में रामकी) में मंगलवार को कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सोमवार से मंगलवार तक करीब 20 घंटे में मशीन ठंडी हुई। इसके बाद मशीन की सफाई और संधारण की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही। इसके बाद पहले चरण की तरह मशीन को रातभर डीजल पर खाली चलाकर तापमान 800 से 850 डिग्री तक पहुंचाया जाएगा। इके चलते बुधवार दोपहर के बाद कचरे को जलाने के लिए मशीन में डाला जाएगा। इस बार 180 किग्रा प्रति घंटे की दर से 55 घंटे में 10 टन कचरा जलाया जाएगा।

ट्रायल के रूप में कचरा जलना शुरू हुआ- हाई कोर्ट के निर्देशानुसार भोपाल में 40 वर्षों से पड़े यूनियन कार्बाइड कचरे के निष्पादन के लिए ट्रायल के रूप में कचरा जलना शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए 27 फरवरी रात्रि 10 बजे से 28 फरवरी दोपहर

तीन बजे तक 17 घंटे मशीन को खाली चलाकर तापमान 800-850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया था और फिर कचरा डालना शुरू किया। तीन मार्च शाम 5.05 बजे आखिरी खेप डाली गई और 5.15 बजे तक करीब 74 घंटों में 10 टन कचरा जलाया गया। इसमें 135 किग्रा प्रतिघंटे की दर से कचरा जलाया गया था। न्यायालय के निर्देशानुसार चार मार्च मंगलवार से दूसरा चरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

लिवर ट्रॉसप्लांट के लिए जमा किए थे 33 लाख रुपये, डिजिटल अरेस्ट गैंग ने ठगे, साइबर हेल्पलाइन ने बचाए 26 लाख

इंदौर। सेवानिवृत्त शिक्षक ने लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो जमा पूंजी एकत्र की थी, उसे साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर ठग लिया। उन्हें मनी लॉड्रिंग, ड्रग्स सप्लाई में लिप्त होने होने का आरोप लगाते हुए पूछताछ करने का झांसा दिया। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने पर अपराध शाखा ने 49 खातों को फ्रीज कर बुजुर्ग के 26 लाख 45 हजार रुपये बचा लिए। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना कनाड़िया रोड निवासी रवींद्र बापट के साथ हुई। 63 वर्षीय बापट के पास पिछले वर्ष नौ सितंबर को साइबर ठग का कॉल आया था। उसने फेड-एक्स कोरियर का अधिकारी बताते हुए कहा कि दिल्ली से मलेशिया भेजा पार्सल कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया है। उसमें 36 फर्जी पासपोर्ट, 140 एमडी ड्रग्स सहित अन्य सामान मिला है। ठग ने बातों में उलझाया और कहा कि इसकी दिल्ली साइबर क्राइम को शिकायत करनी चाहिए। उसने लाइन ट्रांसफर भी कर दी। बात

करने वाले दूसरे व्यक्ति ने दिल्ली साइबर क्राइम का अधिकारी बताया और कहा कि बयान के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। वृद्ध द्वारा इन्कार करने पर वीडियो कॉल पर ही जानकारी लेने की अनुमति दे दी। आधार कार्ड से बैंक खाते लिंक बताकर धमकाया आरोपित ने रवींद्र से आधार कार्ड मांगा और कहा कि इसका सत्यापन करना पड़ेगा। कुछ देर जांच का बहाना कर कहा कि इससे तो कई बैंक खाते लिंक हैं। उनमें अवैध तरीके से करोड़ों रुपयों का लेनदेन (मनी लॉड्रिंग) हुआ है। आरोपितों ने कानूनी कार्रवाई का डर बताया और कहा कि कभी-कभी अपराधी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर लेते हैं। गिरफ्तारी से बचाने के लिए आपसे वीडियो कॉल पर ही पूछताछ होगी। इस दौरान आप किसी से बात नहीं करेंगे। कार्रवाई के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं।" आरोपितों ने दो दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और बैंक में जमा राशि का विवरण पूछा। गिरोह के एक अन्य सदस्य ने आरबीआई अफसर बनकर बात की और कहा कि खाते में जमा राशि ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बापट झांसे में आ गए और 33 लाख रुपये ट्रांसफर करवा दिए।" कुछ समय बाद फोन कट गया और ठग ने बातचीत बंद कर दी। शक होने पर नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई गई।

संपादकीय

पटेल का बयान : निशाना कौन?

मप्र के पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रह्लाद पटेल द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम में जनता द्वारा भीख मांगने की प्रवृत्ति को लेकर की गई टिप्पणी अब उनके गले की फांस बनती जा रही है। विपक्षी कांग्रेस ने तो पटेल की विवादित टिप्पणी पर जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात पटेल के बयान को भाजपा आला कमान ने भी संजीदगी से लेते हुए प्रदेश इकाई से रिपोर्ट तलब करना है। मामला और गंभीर तब हो गया जब पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को टैग करते हुए सफाई देने के अंदाज में एक पोस्ट डाली- 'शुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी?' हालांकि उन्होंने इसे बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक कयास शुरू हो गए कि इस पोस्ट का असली निशाना कौन है और सम्मेलन में गई टिप्पणी भी किसके खिलाफ थी। माना जा सकता है कि प्रह्लाद पटेल ने जो कहा, मूल रूप से उसके पीछे भावना सही थी, लेकिन कहने का तरीका और मंच शायद गलत था। बीते रविवार को राजगढ़ जिले के सुठालिया में लोधी समाज के एक कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता मंच पर जब आते हैं तो लोग माला पहनाते हैं और पत्र पकड़ा देते हैं जिसमें कोई ना कोई मांग होती है। यह अच्छी आदत नहीं है। पटेल ने कहा कि हमेशा मांगने की प्रवृत्ति मत बनाइए। अगर खुद को मांगने की जगह देने वाला बनाएंगे तो खुद भी सुखी होंगे और समाज को भी संस्कारवान बनाएंगे। मंत्री पटेल खुद भी लोधी समाज से आते हैं। उनका यह बयान वायरल होते ही बवाल मच गया। सवाल पूछा जाने लगा कि पटेल जनता से क्या देने की अपेक्षा रखते हैं। जनता लोकतंत्र की सबसे कीमती चीज वोट देकर ही नेताओं को चुनती है, उन्हें पदों पर बैठाती है। उसके बदले में लोग नेताओं से अपने काम कराने की अपेक्षा रखते हैं तो इसमें गलत क्या है? कांग्रेस ने तो पटेल के बयान की आलोचना करते हुए इसके खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उधर पटेल ने अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि 'मेरे मन में जनता सदैव जनार्दन रही है। उसने नकारा हो या स्वीकारा हो, ये मेरी निष्ठा का अतीत है वह आज भी है। लेकिन शुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी।' ये पोस्ट उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी टैग की और थोड़ी देर बाद ही उसे हटा भी लिया। कांग्रेस प्रवक्ता अमित टेवरे ने कहा कि मंत्री पटेल द्वारा जनता को भिखारी बताना जनता का अपमान है। उन्होंने मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले को कोर्ट में ले जाएगी। प्रहलाद पटेल के बयान पर उनकी अपनी पार्टी भाजपा में खलबली मच गई। भाजपा आला कमान ने इसको लेकर पार्टी की प्रदेश इकाई से रिपोर्ट मांगी है। अगर इस टिप्पणी को भाजपा सरकार और पार्टी की नीति के खिलाफ माना गया तो पटेल पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि जनता को भिखारी बताकर परोक्ष रूप से पटेल अपनी ही पार्टी भाजपा की सरकारों की जनता को नकद बांटने वाली उन 'कल्याणकारी योजनाओं' पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें आलोचक रेवड़ी कल्चर मानते हैं। अब सवाल यह कि पटेल जैसे अनुभवी नेता ने ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे पार्टी आला कमान द्वारा उन्हें मप्र का सीएम न बनाने की कसक है या कुछ और? यह समझना मुश्किल है कि यदि इसके पीछे पटेल का निजी असंतोष है तो उसमें जनता को आड़ बनाने की क्या जरूरत थी।

मंत्री के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान

अशोक भाटिया

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा राजनेताओं और अपराधियों की मिलीभगत का जीवंत व ताजा उदाहरण है। यह सांठगांठ इस हद तक है कि धोखाधड़ी, कमिशनखोरी, रंगदारी वसूली, मारपीट और हत्याओं तक बात पहुंच जाती है। आरोपों से लगता है कि धनंजय शायद इसी जाल में फंसे हैं। बीड़ जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या इसी कड़ी का हिस्सा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड और उनके गिरोह के साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनसे अपनी करीबी कबूल कर धनंजय भी गिरफ्त में आ गए। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा था। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए फडणवीस ने कहा, 'महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल के पास भेज दिया है।'

यहां बीड़ जिले में स्थित मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की पिछले साल दिसंबर में बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुंडे के करीबी वाल्मिक कराड को को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें साफ दिखायी दे रहा है कि सरपंच को कैसे पहले निर्वस्त्र किया गया। फिर उन्हें बेरहमी से पाइप और दूसरे हथियारों से पीटा गया। एक तस्वीर में दिख रहा है कि सरपंच देशमुख अधमरी हालत में पड़े हुए, तब उन पर आरोपी सुदर्शन घुले ने पेशाब भी किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी वाल्मीकी कराड एनसीपी नेता और मंत्री धनंजय मुंडे का खास आदमी बोला जाता है।

इस मामले में कांग्रेस विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने हत्याकांड से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए महायुति सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 'बीड कांड में हैवानों की ये तस्वीरें और वीडियो पिछले 2 महीने से राज्य के गृह मंत्री, उपमुख्यमंत्री के पास थीं। और फिर भी आपने धनंजय मुंडे का इस्तीफा न लेकर नैतिकता की हत्या कर दी!' उन्होंने आरोप लगाया कि 'पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी बंद करने के बाद वाल्मिक कराड को पुलिस हिरासत में सभी पांच सितारा सुविधाएं दी गईं। ये सब क्यों? जहां महागठबंधन के मंत्री धनंजय मुंडे के खासमखास और उनके बिना इस मंत्री का पन्ना नहीं हिलता, वहीं हैवान वाल्मीक कराड और उनके साथियों पर गृह मंत्री, उपमुख्यमंत्री और पुलिस का लाड़-प्यार था। पूरे महाराष्ट्र को गुस्सा दिलाने वाली संतोष देशमुख की हत्या की तस्वीर अब महाराष्ट्र के सामने आ गई है। लेकिन इस सरकार ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस्तीफा देने में बहुत देर हो चुकी है, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए!'

गौरतलब है कि इतने लंबे समय तक, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अजीतदादा पवार के वाहन के साथ एकजुट एनसीपी की राजनीतिक चुनौती को कुचलने की कोशिश की। एनसीपी विभाजित थी। भाजपा की रणनीति सफल रही। अब भाजपा अजितदादा और उनकी एनसीपी के अस्तित्व को कुचलने के लिए उसी बर्तन का इस्तेमाल करेगी, जिनके पैर वहां थे। मीडिया ने पहले ही संकेत दिए थे कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा ले लिया गया था।पहला संकेत यह है कि मीडिया ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच होने लगी है। यह अंतिम नहीं है, बिल्कुल। अब इस सरकार के माणिकराव कोकाटे इसका शिकार होंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्रियों के कुछ मामले सामने आएं तो चौंकिएगा मत।

यह एक काले पत्थर पर एक रेखा थी जिसे उन्हें उन्हें देना था। मीडिया ने कुछ समय से मुंडे को मंत्रिमंडल से हटाने की आवश्यकता व्यक्त की थी और कहा था कि यदि वह या उनके नेता अजितदादा अपने आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि मुंडे को उनका हाथ पकड़कर निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। मुंडे ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है। इसमें महीनों नहीं लगे होंगे। धनंजय मुंडे का इस्तीफा तब लिया गया जब यह महसूस किया गया कि उनका मामला बहुत गंभीर होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस मुंडे और अजीतदादा के लिए ऐसा समय लेकर आए। यह मुंडे महाभारत पिछले तीन महीने से चल रही है।

मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर इसे 'अजीतदादा का फैसला' बताया। यानी अजीतदादा को यह तय करना चाहिए कि मुंडे को मंत्रिमंडल में रखना है या नहीं क्योंकि वह अजितदादा की पार्टी के हैं। सिद्धांत रूप में या कागज पर, यह उचित है, लेकिन केवल कागज पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 'आप इस्तीफे के बारे में देखते हैं' का रुख अपनाया है, लेकिन साथ ही, उन्होंने भाजपा विधायक सुरेश दास या कथित सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया को चुप करा दिया, जो मुंडे के पीछे हाथ धो रही थीं। नहीं। दमानिया की बात को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। क्योंकि वह भाजपा की आधिकारिक सदस्य नहीं हैं। लेकिन दास के बारे में क्या? मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष हित हो भी सकता है और नहीं भी; लेकिन फडणवीस का आशीर्वाद दास के लिए निश्चित था।

फडणवीस ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराई और एक सार्वजनिक बयान दिया और दास को अवाक रखा। यही बात दमानिया के साथ भी है। भले ही वह आधिकारिक तौर पर भाजपा से नहीं हैं, लेकिन उन्हें मुंडे के खिलाफ इतने दस्तावेज और 'अंदरूनी जानकारी' कैसे मिली। दूसरी तरफ पार्टी के बाहर से दमानिया और तीसरी तरफ मीडिया मुंडे के खिलाफ रैली करती रही और यह केवल तभी हुआ जब यह सुनिश्चित हो गया कि यह जारी रहा कि मुंडे को पद छोड़ना पड़ा। यह पढ़कर कोई भी हैरान रह जाएगा कि सीएम फडणवीस ने मुंडे को पहले ही नारियल क्यों नहीं दिया?

इसका सीधा सा जवाब है: मुंडे जितने लंबे समय तक कैबिनेट में रहेंगे, भाजपा के लिए यह उतना ही सुविधाजनक होगा कि वह उन पर और उनके संरक्षक अजितदादा के सफेद कुड्डा पर अधिक से अधिक सींग फेंकते रहें। अगर अजितदादा और उनके सहयोगी खुद कीचड़ उछाल रहे हैं, तो भाजपा उन्हें क्यों रोके? वास्तव में, अगर फडणवीस ने इसे अपने दिमाग में लाया होता, तो मुंडे को घर भेजा जा सकता था और मामला कभी शांत नहीं हो सकता था। लेकिन फिर वह राजनीति क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवस्था करके कि सत्तारूढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ आग सत्तारूढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ आग को हवा देना जारी रखेगा, फडणवीस ने एक पार्टी को एक पत्थर में और दूसरे को उड़ाने के लिए अधिक शक्ति दी। जिस पार्टी को चोट लगी थी, वह निश्चित रूप से अजितदादा की राष्ट्रवादी है। और जिस पार्टी में उड़ान भरने की अधिक ताकत है वह विपक्ष है। यह मामला अब मुंडे तक सीमित नहीं रहेगा। धनंजय मुंडे अजीतदादा की ढाल थे। अब जब इसे हटा दिया गया है, तो अजीतदादा विपक्ष के चरण में होंगे। उनका इस्तीफा टालकर उन्होंने एक तरह से उन्हें बचाने की कोशिश की, जिससे विपक्ष के हमले और तेज हो गए। यह एक बाघ की तरह है। एक बार जब यह मानव रक्त का स्वाद लेता है, तो इसे नरभक्षी बनने से रोकना मुश्किल होता है। राजनीति में एक बार सत्ताधारी दल का कोई मोहरा मारा जा सकता है तो नए शिकारी की तलाश में विपक्ष को रोकना मुश्किल होता है।

और यहां, अजितदादा की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना संभावित शिकारियों की सेना से लैस हैं. मुंडे के बाद अब नंबर कोकाटे होगा। अदालत ने निःसंदेह उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है और अगर उनकी सजा पर रोक लगा दी जाती है, तो भी यह उनके खिलाफ दोष नहीं मिटाता है। इससे पहले जब सुनील केदार व अन्य के लिए समय आया तो सत्ता पक्ष ने उन्हें तत्काल नारियल देने की तत्परता दिखाई थी। इसलिए अब कोकाटे को बचाना मुश्किल है। इसका मतलब है कि पहले छह महीनों के भीतर अपराध और भ्रष्टाचार के कारणों से फडणवीस कैबिनेट के दो सदस्यों को घर भेजने का समय होगा। ये दोनों अजितदादा की एनसीपी से हैं। वहीं, साफ है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भी बीजेपी का दबाव बढ़ेगा।

एक बात तो यह है कि उन्हें मनचाहे जिलों का संरक्षक भी नहीं दिया गया है. फडणवीस ने तानाजी सावंत, दीपक केसरकर और अब्दुल सत्तार जैसे नेताओं को दूर रखा, जो पार्टी के 'सर्व-संसाधन' हैं। दूसरी ओर, नई सरकार में शिंदे-सेना के पूर्व मंत्रियों के कई फैसलों को उलट दिया गया और कुछ की जांच की घोषणा की गई। अगर शिवसेना ने उचित सबक नहीं लिया, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग 'मुंडे' नहीं होंगे। दूसरा, धनंजय मुंडे के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद अजीतदादा की एनसीपी भी शिंदे-सेना में किसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी सक्रियता दिखाएगी। ताकि भाजपा को जरूरत का गोला-बारूद मिल जाए और वह विपक्ष तक आसानी से पहुंच जाए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए और संभावित भाजपा विपक्ष को चुप करा दे दे तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। 'आने-जाने' वाले एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार के बाद भाजपा के लिए बाहरी लोगों को खुश रखने से ज्यादा जरूरी उन्हें गले लगाना है।

इसे काव्यात्मक न्याय कहा जाता है। वही धनंजय मुंडे सच्ची कहानी सुनाकर खुश थे कि कैसे शरद पवार ने हाल तक अजीतदादा के साथ अन्याय किया था। मानो कथित अन्याय के निवारण की जिम्मेदारी उनके सिर पर है! अब उनके पास इस अन्याय को दूर करने के लिए केवल समय होगा। इन लोगों ने राजनीति में जो बोया है, वही उगने लगा है और यही उनको मिलने वाला है।

एआई : घोड़ा बिना लगाम का नहीं हो

दुनिया मेरे आगे

जवाहर चौधरी

लेखक स्तम्भकार हैं।

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) शब्द सामान्य जन की बातचीत में चिंता के साथ शामिल हो गया है। रोज एआई के चौंकाने वाले कारनामे खबरों में आ रहें हैं। कहा जा रहा है कि एआई रोबोट से जुड़ कर वो तमाम काम कर लेगा जो इंसान करते हैं। इंसान को तो हम जानते ही हैं, सारे काम तो अच्छे करता नहीं है। बल्कि यों कहें कि अब गैर-इंसानी काम ज्यादा करने लगा हैं तो गलत नहीं होगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर चली की एक रोबोट ने अपनी मालकिन को मार डाला! एक विचार यह भी चल रहा है कि एआई संपन्न रोबोट अपनी तरह के रोबोट खुद बनाने लगेगा। जैसा की प्रकृति ने प्राणियों को यह शक्ति दी है कि वह अपने तरह का प्राणी बना लेते हैं। लेकिन अब मशीन ऐसा कर लेगी तो हैरत की बात है। यानी रोबोट अपनी जनसंख्या बढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये रोबोट अब सैनिकों की जगह युद्ध लड़ेंगे। पुलिस की तरह वह सारे काम करेंगे! वे सड़क पर ट्रैफिक का नियंत्रण करेंगे, वाहनों की स्पीड चेक करेंगे, चालान बनाएंगे और पैसा वसूलेंगे। बड़ी इमारत/मॉल वगैरह की चौकीदारी भी इनके जिम्मे होगी और यदि कोई संदिग्ध आदमी नजर आया तो उसे मार भी सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने का निर्णय एआई सज्जित प्रणाली खुद ले लेती है। जैसे मिसाइल का पता लगाकर उसे नष्ट करने का यांत्रिक निर्णय। दुश्मन के खिलाफ यह रक्षात्मक है, लेकिन मशीन कब पोरस का हाथी हो जाए इसके डर से इंकार नहीं किया जा सकता है। कल्पना की उड़ान यहां तक जाती है कि वह समय दूर नहीं जब एआई रोबोट हम पर राज करने लगेंगे। इंसान रोबोट पर पहले निर्भर होगा उसके बाद गुलाम हो जाएगा। इसका असर यह भी हो सकता है कि रोबोट हिंसक हो जाए, या अपने विवेक या प्रोग्रामिंग के हिसाब से जरूरी समझेंगे तो आदमी को खत्म ही कर दे।

इन दिनों विध्यार्थी एआई तकनीक पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई में इनसे मदद मिलती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। और यह काम बहुत ही फटाफट यानी चुटकियों में हो जाता है। हम अपने सामान्य जीवन के कार्यों में हिसाब किताब जोड़ घटाव करने के लिए कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। हमारे बीच से वह पीढ़ी जा चुकी है जो बिना कैलकुलेटर के केवल मुंह जबानी सारा हिसाब जोड़ घटाव कर लेती थी। पौवा-अद्धा-पौना, पहाड़े सबको याद थे। अब अगर एआई के सहारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, शोध के पेपर तैयार किए जाएंगे तो इससे विद्यार्थियों की रचनात्मक और मौलिकता कम होगी, विचारों को विकसित होने के अवसर कम हो जाएंगे। पेपर और फाइलों में बच्चे अच्छा करते दिखेंगे लेकिन हकीकत की जमीन पर वह बहुत पीछे रहेंगे।

इस समय उक्त विचार हमें अतिश्योक्ति पूर्ण लग सकते हैं लेकिन देखें कि इन दिनों हाल क्या है। आज लगभग हर हाथ में मोबाइल फोन है। इसमें हमारे बैंक अकाउंट, निजी जानकारी, फोटो वगैरह सब है। हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जो देखते हैं उससे हमारी गतिविधि दर्ज हो जाती है। कहां होती है, कौन करता है, यह हम नहीं जानते हैं। लेकिन जल्द ही फोन पर आपकी सर्च के अनुसार साइट्स खुलने लगती हैं। आपने बिजली के पंखे को सर्च किया तो अगले कुछ दिनों तक आपको पंखे दिखाते रहेंगे, जब तक कि आपकी पंखों की खरीदी दर्ज न हो जाए। अकाउंट में पैसा जमा होता है और इन्वेस्टमेंट के प्लान सामने आने लगते हैं। दवाई से लगाकर जूते तक कुछ भी आपने देखा कि घेरे गए। निजत्व को लेकर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। आप कहां इस्तेमाल किया जा रहे हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं आपको ही पता नहीं है। यह निजता का उल्लंघन है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना सामान्य जीवन संभव नहीं है। लेकिन फेक न्यूज़ और फेक वीडियो की इतनी भरमार है कि हम भ्रमित व डरे हैं। एआई से दिवंगत-जनों को चलते फिरते बात करते देखा जा सकता है। एआई की हरकत है कि सोशल मीडिया से तस्वीर लेकर किसी भी आदमी को कुछ भी करते हुए दिखाया जा सकता है। और यह कार्य प्राय अश्लील ही होते हैं। इससे अच्छे भले व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती है।

एआई पूरी तरह से प्रभावशील हो उससे पहले इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इस हेतु जरूरी शोध होने चाहिए और कानून भी बनाना चाहिए। जैसे समाज भले व्यक्तियों और अच्छे कामों को प्रोत्साहित करता है और बुरे व्यक्तियों और बुरे कामों को हतोत्साहित करता है इसी तरह एआई के अच्छे पक्ष को बढ़ाना चाहिए लेकिन नुकसान देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश करना चाहिए। लोगों को भी एआई के प्रति जागरूक और सावधान होना होगा। घोड़े की सवारी बिना लगाम के खतरनाक होती है।

स्त्री अस्मिता पर प्रश्न और आधुनिकता

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तम्भकार हैं।

महिला दिवस के अवसर पर हर तरफ आज महिलाओं को बधाइयों का सिलसिला लगा हुआ है। यह बात सही है कि आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि यह निश्चित है कि जो आज है वह कल नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे समाज में स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति पहले थी, आज वैसी नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों को उनके अधिकार पूरी तरह मिल चुके है पर वह अधिकार मिल कैसे सकते है जबकि स्वयं स्त्रियां ही अपनी साथ द्वेष रख रही है। पुरुषों के कदम से कदम मिलाने की होड़ ने उनके ही कदमों में लालच की कंपन को मिला दिया है, ऊपर से आधुनिक होने की होड़ ने करेले पर नीम का काम किया है। घर के काम हमें चुभने लगे है, कपड़े और सोच छोटी होती जा रही है। हम यूरोपीय देशों की नकल करने में यह भूल गए है कि भारतीय स्त्री प्राचीन काल से ही आधुनिक रही है। हमारे इतिहास को गौरान्वित करती महिलाएं जैसे गार्गी, अरुंधती विश्वआरा , घोषा, लोपामुद्रा ऐसी ना जाने कितनी स्त्रियां है जिन्होंने अपनी आधुनिक सोच के चलते भारत का नाम रोशन किया। हमारे समाज में स्त्रियों को अपना वर चुनने का अधिकार रहा है लेकिन समय ने अपनी करवट बदली और पुरुषों ने अपने अधिकार क्षेत्र को बड़ा कर लिया। इसका सीधा असर महिलाओं के जीवन पर भी पड़ा लेकिन महिलाओं के भीतर की आग को कोई कम न कर सका है। इसी ज्वाला से निकली झांसी की रानी, झलकारी बाई, नीरा आर्या, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सूचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भारत का नेतृत्व किया। यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। इंदिरा गांधी से लेकर, कल्पना चावला, मैरी काम से लेकर निर्मला सीतारमण और कैप्टन शिवा चौहान और ऑन ड्यूटी शहीद होने वाली पहली महिला भारतीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट किरन शेखावत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वह इतिहास इसलिए रच सकी क्योंकि उन्होंने अपने आधुनिक होने का प्रमाण पत्र किसी से लिया नहीं और ना ही किसी को यह अधिकार दिया कि वह उनकी काबलियत को किसी तराजू में तौल सके। उन्होंने आधुनिकता को एक अलग नज़र से देखा। उनके लिए आधुनिकता किसी रील पर मटकने या पुरुषों को नीचा दिखाने का नाम नहीं था, बल्कि एक अवसर था जिससे वह स्वयं को संवार सकें।

मैं यह नहीं कहना चाहती कि छोटे कपड़े पहनना गलत है। यह किसी का भी निजी फैसला हैलेकिन पब्लिक प्लेटफार्म पर मॉडर्न होने के नाम पर जिस प्रकार की रील बनाई जा रही है क्या वह सच में आधुनिकता है? अगर कोई रोक दें तो हम कहते है कि अपनी सोच बदलें, क्या सच में यह कह देना काफी है? छोटी -छोटी बातों में तलाक ले लेना, दहेज के झूठे आरोप लगाना और कई बार रेप के भी गलत आरोप लगाकर किसी भी परिवार को लगभग तबाह कर देना यह आम होने लगा है। कई बार लगता है जैसे महिलाओं के भीतर की ज्वाला ने अपना रूप बदल लिया है। बदले की भावना ने उनके भीतर की ताकत ने एक द्वेष की जगह बना ली है। अब वह हर किसी से बस बदला लेना चाहती है। हाल ही में एक पीड़ित पुरुष ने जब अपनी पत्नी से तंग आकर आत्महत्या की तब वह अपने पीछे एक वीडियो और लम्बा पत्र लिख कर गया। फेमिनिज्म के नाम पर कुछ महिलाओं ने मीडिया पटल पर आकर उस पुरुष को ही टेटीड कह दिया। यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि ऐसी कई घटनाएं है। तलाक के बाद पार्टी करना आम हो गया है। हम अपने आपको किस ओर ले जा रहे है, यह सोचने की बात है।

यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि समाज का संतुलन बिगाड़ने में महिलाओं का ज्यादा हाथ है बल्कि यह वह आग है जो पुरुषों के बेहद गलत व्यवहार के कारण उभर रही है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे कुछ गलत कदमों से उन स्त्रियों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिन्हें महिला कानूनों की विशेष आवश्यकता है।

आज भी भारत के कई हिस्सों में महिलाएं पुरुषों की प्रताड़ना झेल रही है, लेकिन उनकी आवाज़ तब दब जाती है जब अन्य महिलाओं के फेक केस सामने आते है। हर वर्ष की तरह हम इस वर्ष भी महिला दिवस धूमधाम से मनाएंगे पर अगले दिन एक लम्बा मौन हमारी प्रतीक्षा करेगा जबकि ज़रूरत है कि हम महिला दिवस को ग्लोरिफाई करने की अपेक्षा उन महिलाओं की सहायता करें जो आज भी उम्मीद की एक किरण का इंतजार कर रही है।

हम आधुनिक और मॉर्डन हैं। बस हमें अपने भीतर से पुरुषों की बराबरी की होड़ को खत्म करना होगा क्योंकि जिसे हम धरती पर लाए हैं, हम उससे बराबर कैसे हो सकती हैं? हम तो पहले से ही आगे है। अपने भीतर की कुछ जटिलताओं को मिटाना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी राष्ट के निर्माण में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हमें समाज को संवारने के लिए अपने आपको संवारना होगा। HE और SHE में S, H से आगे इसलिए है क्योंकि S IS SUPERIOR THEN HE पर जब तक हम अपने ही समाज के एक हिस्से को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, तब तक हम अपना भी कुछ नहीं अच्छा कर पाएंगे। इस महिला दिवस एक नई सुबह का आगाज़ करें जिसमें हम तो बेहतर है ही। बस अपने साथ-साथ अपनों को भी बेहतर बनाने का कार्य करें जिससे हम पर प्रश्नचिंह ना लगे, बल्कि हर प्रश्न का उत्तर ही हम हो।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेस प्रा. लि., राउखेड़ी, देवास रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक - उमेश त्रिवेदी
संपादक (म.प्र.) -विनोद तिवारी
कार्यकारी प्रधान संपादक - अजय बोकिल
स्थानीय संपादक - हेमंत पाल
प्रबंध संपादक - अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं!

व्यंग्य

संजय तेलंग

वरिष्ठ पत्रकार और व्यंग्यकार

फिल्मों के गीत पहले अर्थपूर्ण तो होते ही थे, उनमें अहम संदेश भी छिपा होता था। ऐसे अनेक गीत आपको सुनने को मिल जाएंगे। पर, आज के फ़िल्मी गीतों में वह बात नहीं रही। आजकल तो दर्शकों-श्रोताओं की परीक्षा लेते, दोहरे अर्थ वाले गीत लिखे जा रहे हैं। हम दोहरे अर्थ वाले गीतों में न उलझते हुए, अर्थपूर्ण गीत की ही बात करेंगे। बरसों पहले आई हिन्दी फिल्म अमानत के एक गीत 'मतलब निकल गया है, तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं' में गुलुकार साहिर ने कितनी सटीक बात कही है। यह गीत आज भी जब फिजा में गूंजता है, तो सुनने वाला हर व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, कि अरे, यह गीत तो उसकी ही कहानी बयां कर रहा है। यह सही भी है क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति का कभी न कभी ऐसे मतलबियों से साबका पड़ ही जाता है। वे मीठी मुस्कान बिखेरते हुए मिलते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और अपना काम निकाल कर चलते बनते हैं। ऐसे मतलबियों को पहचानना आसान काम नहीं है, इसलिए इनसे बचना भी संभव नहीं हो पाता। लोग ऐसे लोगों की बातों में आकर अनजाने में ही उनका स्वार्थ सिद्ध करने में सहयोगी बन ठग लिए जाते हैं।

इस तरह के लोग कहीं भी मिल सकते हैं रास्ते में, कार्यालयों में, मंदिरों में, बसों में और रेलों में भी। मान लीजिए आप रेल में सीट पर बैठ कर यात्रा कर रहे हैं, तभी आपको गोद में बच्चा उठाए एक यात्री खड़ा दिखाई देगा। उसके पास सामान होगा और साथ में उसकी पत्नी भी खड़ी होगी। पति-पत्नी के चेहरे से मासूमियत टपक रही होगी। अब दोनों आपकी ओर याचक की नजर से देखेंगे। कातर मुस्कान भी फेकेंगे। इसका सीधा अर्थ है, वे कष्ट में हैं और आप उनके विघ्नविनाशक बन सकते हैं। धीरे-धीरे आपको उनकी परेशानी का अहसास होने लगेगा। आपका चेहरे पर आपके मन के भाव पढ़ते ही, वह यात्री अपनी पत्नी के लिए थोड़ी सी जगह मांगेगा। उसका कातर स्वर आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा और आप इंकार करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा सिमट कर आप जगह बना देंगे। पत्नी के सीट पर बैठते ही उस यात्री के चेहरे पर आधा युद्ध जीत लेने का सुकून दिखाई देने लगेगा। थोड़ी देर में बच्चा पत्नी की गोद में होगा और उसे नींद आने लगेगी।

अब उस महिला का आपसे निवेदन होगा कि भाई साहब थोड़ी सी जगह और दे दें, बच्चे को लिटा लेंगे। महिला के निवेदन को कभी कोई टाल नहीं सका! आप फौरन थोड़ा और सिमटकर उकड़ू बैठ जाएंगे। बच्चे को ठीक से सीट पर लेटाने के बाद, अब महिला पति से कहेगी आप भी थोड़ा बैठ जाइए, कब से खड़े हैं, थक गए होंगे। वह आपसे अनुमति लिए बिना ही पति के लिए भी जगह बना लेगी। पति के बैठते ही आपको और अधिक सिमटना होगा। अब परेशान होने की बारी आपकी होगी। परोपकार कर परेशानी उठाते हुए यात्रा करना ही अब आपकी नियति बन जाएगी। आप मन मसोस कर भी विचार करेंगे चलो आपकी वजह से किसी की परेशानी तो कम हुई। आप जब यह सोच रहे होंगे, तभी आपका और साथ ही उस दंपति का स्टेशन आ जाएगा। हद की पराकाष्ठा देखिए पति-पत्नी बिना आपका आभार माने सामान सहित तेजी से उतर जाएंगे और आप थके-हारे अपना सामान समेट कर उतर रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता साहिर साहब ने 'मतलब निकल गया ....' गीत इसी अवसर के लिए ही लिखा था!

इस तरह के मतलबी लोग कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। वर्तमान दौर में भी ऐसी लोगों की कमी नहीं है। वैसे इस तरह के मतलबी लोगों की नई जमात अब समाज में देखी जाने जा रही है। इनके चंगुल से बचना तो संभव ही नहीं है। क्योंकि, इन्हें आसानी से पहचानना संभव नहीं है। इस जमात के लोग अपने आपको शान से 'प्रोफेशनल' कहलाना पसंद करते हैं। मूल रूप से ये बरसों से चली आ रही, उसी मतलबी कौम के जीन से पैदा हुई जमात है। इनका काम इतनी सफाई से होता है कि आप जान भी नहीं पाते कि आप उनके काम आ चुके हैं। अब प्रोफेशनल की फितरत भी जान लें। 'जिससे काम उसी से व्यवहार, बाकी सब बेकार .... !' प्रोफेशनल का शिकार होने से बचने के लिए इन्हें समय रहते पहचानने के तौर-तरीके सीख लें और कदापि फायदा न उठाने दें या फिर सौ की सच्ची बात तो यही है कि आप भी प्रोफेशनल हो जाएं!

प्रसंग

सीमा जयंत भिसे

लेखिका और समाज सेविका

वंदे मातरम् की रचना को 150 साल पूरे हुए

वंदे मातरम् गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था, जिसे 150 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्र को मां के रूप में वंदन करने का यह अनूठा और बिरला प्रयोग था, जो स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र बना गया। इसका अर्थ है 'मातृभूमि तुझे प्रणाम!' इस गीत में राष्ट्र को मां का दर्जा दिया गया, जो विश्व में अन्य कहीं नहीं है। यह गीत लिखते समय विशाल भारत बंकिम चंद्र के आंखों के सामने था। यह केवल क्रांतिकारियों के लिए नहीं था। इसमें स्वराज से सुराज की ओर जाने का स्पष्ट संदेश भी है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र का इतिहास जानना और समझना जरूरी है। यह अनिवार्य भी है और अपरिहार्य भी। कई लोगों को लगता है जो पूर्व में घटित हो गया, उसका पुनः स्मरण आवश्यक नहीं है। लेकिन, जो राष्ट्र अपना इतिहास भूलते हैं, उनका वर्तमान सुदृढ़ नहीं हो सकता। साथ ही उस राष्ट्र का भविष्य भी उज्ज्वल नहीं रहता। इसी तरह 'वंदे मातरम्' शब्द मात्र नहीं है, अपितु यह भारत के स्वतंत्रता का स्वर्णिम इतिहास का गवाह भी है। यह बात जिसने समझ ली, उसे भारत की नस पकड़ में आ गई। उसे इस राष्ट्र की समस्या भी समझ में आ सकती हैं। वंदे मातरम् स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र है। इसीलिए इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। 'वंदे-मातरम्' शब्दों के लिए क्रांतिकारियों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इन दो शब्दों में राष्ट्र निर्माण करने की क्षमता है। यह केवल क्रांति तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ विस्तृत है। इसमें हमारे संस्कृति के दर्शन, अध्यात्म की अनुभूति और परमार्थ का प्रकाश है। इसमें स्वराज से सुराज्य की ओर जाने का संदेश है।

सन् 1875 में यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। जिसे बंगाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। देश में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा था। क्रिश्चियन मिशनरी मानवीय कार्य के आधार पर गरीबों की सेवा करने के बजाय शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे। दूसरी और मुसलमानों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। धर्मांतरण से देश की अखंडता और अस्तित्व को खतरा था। अलग-अलग माध्यम से हिंदुओं को बांटने का एक सूत्री कार्यक्रम क्रिश्चियन और मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा था। कोई धौंस देकर तो कोई शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा देकर। इसलिए हमारे धर्म की, हिंदुओं की रक्षा करना यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं है। यह देश के हिंदुओं के अस्तित्व का प्रश्न है। यह बात उस समय के सभी समाज सुधारक और क्रांतिकारी समझते थे।

अंग्रेजी सत्ता का पदार्पण भारत में होने के बाद मात्र एक शतक में ही भारत की स्थिति दयनीय हो गई। अपनी मातृभूमि की स्थिति एक महामानव से देखी नहीं गई। उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। यह देखकर उनके हृदय में पीड़ा हुई, उन्होंने सोचा मैं क्या करूं जिससे मेरी मातृभूमि पुनः शक्तिशाली होगी फिर से मातृभूमि को स्वराज प्राप्त होगा। बंकिमचंद्र ने संस्कृत का गंभीर अध्ययन किया। कालिदास से उन्हें विशेष प्रेम हो गया। उस समय संस्कृत के महापंडित हलधर तर्क चूड़ामणि इस बुद्धिमान विद्यार्थी से मिलने कंठाल पाड़ा आया करते थे। बंकिमचंद्र का संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अधिकार था। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। कुछ साल तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। अंग्रेजों को अपने आप पर बहुत घमंड था। आज भी उनकी काले गोरे में भेद करने की नीति को सारी दुनिया जानती है। बंकिम चंद्र बहुत संतुलित व्यक्ति थे। अंग्रेज अधिकारियों के विरोध में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

एक दिन बंकिमचंद्र कार्यालय का काम समाप्त कर, बग्गी से लौट रहे थे। दरबान पास के रास्ते से बग्गी ले जा रहे थे। जो रास्ता रोज का नहीं था। उस रास्ते पर लेफ्टिनेंट कर्नल डफीन और उनके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। अपने सामने से एक भारतीय बग्गी से जा रहा है, यह डफिन को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसने चालक को गालियां देना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों की मानसिकता बंकिम चंद्र जानते थे। वह उतर गए और डफीन को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। इसका परिणाम उल्टा हुआ। वो अधिक गुस्सा हो गये और उन्होंने बंकिम जी को धक्का दे दिया। बंकिम जी को काफी चोट आई ।

वे घर आए और निश्चय किया की डफीन को अच्छा सबक सिखाएंगे। दूसरे ही दिन डफिन पर फौजदारी का मुकदमा दाखिल कर दिया। डफीन आग बबूला हो गए और पागल जैसी हरकत करने लगे। उस समय इन गोरे लोगों की तरफ भारतीयों की गर्दन उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। बंकिमचंद्र को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धोंस डपट का सामना करना पड़ा। परंतु वह पर्वत की तरह अविचल थे। डफीन ने बंकिम पर हाथ उठाया, यह देखने वाले कई लोग थे। सारे गवाह डफीन के विरोध में थे। अंत में डफीन ने बिना शर्त लिखित में माफी मांगी। यह बंकिम चंद्र की बड़ी विजय थी।

26 जून 1838 को बंकिमचंद्र चटर्जी का जन्म बंगाल के कंठाल पाड़ा में एक समृद्ध बंगाली परिवार में

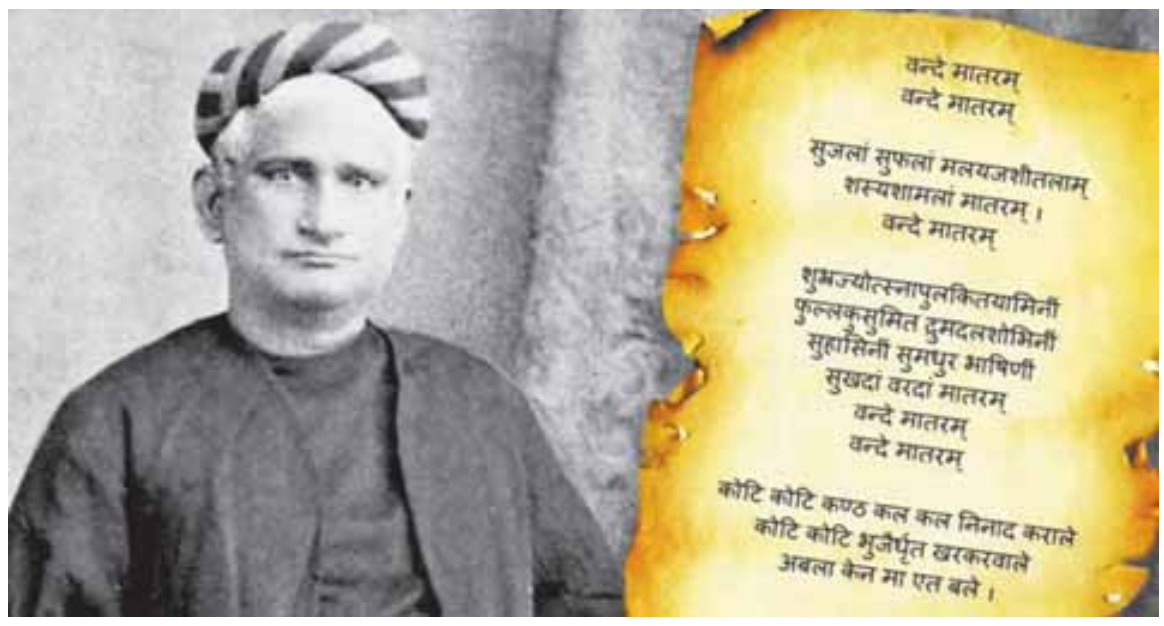

हुआ। इनकी मां का नाम दुर्गा सुंदरी और पिता का नाम जादव चंद्र था। बंकिमचंद्र 5 भाई बहनों में से एक चौथे नंबर के थे। पिताजी के कारण ही बंकिमचंद्र जी को ज्योतिष, इंद्रियों की शक्ति, काव्य, संगीत, प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम उपजा। आगे उन्होंने एक उपन्यास पिता को समर्पित करते हुए लिखा 'हिंदू धर्म के मूल तत्व जिनसे मैंने सीखें, वो मेरे आदरणीय पिता को समर्पित!' बंकिमचंद्र जी ने 27 वर्ष की आयु में 'दुर्गेश नंदिनी' नामक उपन्यास लिखा। फिर बंग-दर्शन नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1875 में वंदे मातरम् यह गीत लिखा। बाद में इसे आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में योगदान दिया। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान और उन पर तरह-तरह के अत्याचार। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम् मंत्र ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई चेतना से भर दिया। आनंद मठ में जो संघर्ष दिखाया गया वह ऐतिहासिक था। इसकी पृष्ठभूमि पर भी हमें ध्यान देना होगा।

संन्यासियों का आंदोलन इतिहास में प्रसिद्ध है। सन 1762 से 1774 यह इस आंदोलन का कालखंड है, जो बंगाल में घटित हुआ। यह सन्यासी कौन थे? इसका इतिहास में कोई कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु वारेन हेस्टिंग्स के एक पत्र के अनुसार ये संन्यासी हिंदू थे यह ज्ञात होता है। यह लोग हिंदुस्तान के यायावर थे, जो अत्यंत साहसी तथा अदम्य उत्साही थे। ऐसा इस अंग्रेज का कथन है। सरकारी अहवाल के अनुसार ये संन्यासी तिब्बत के दक्षिण भाग में काबुल से चीन तक फैले पहाड़ी प्रदेश में रहते थे। दूसरे अर्थ में यह पूर्ण प्रदेश उनके आधिपत्य में था। 1772 में पूर्णिया, तिरहुत तथा दिनाजपुर के अंदर घुसकर चढ़ाई की और रंगपुर के पास ब्रिटिश और मुसलमानों की संयुक्त सेना को बड़ी मात दी। वास्तव में संन्यासियों के इस आंदोलन को योग्य नेता मिल जाता, तो ब्रिटिश सरकार को परिणाम कारक चुनौती देने में सक्षम हो सकता था। परंतु उनकी संस्था ज्यादा आगे चल नहीं सकी। संन्यासियों के इस आंदोलन का उपयोग बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास 'आनंद मठ' में उत्कृष्ट रूप से किया। आनंद मठ में चित्रित संतान एवं उनके आंदोलन का वारेन हेस्टिंग्स के विद्रोही संन्यासियों के वर्णन से हूबहू मिलता है। उस समय अंग्रेजों ने अपने तरीके से और मुस्लिमों ने अपने तौर तरीकों से हिंदू प्रजा का जीना दूभर कर दिया था। इस परिस्थिति के प्रतिकार स्वरूप संन्यासियों का आंदोलन हुआ। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित 'आनंद मठ' में चित्रित आंदोलन हिंदू संगठनों का है। यह मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध भी था, इसे ऐतिहासिक सत्य ही कहा जाना चाहिए।

आनंद मठ की कथावस्तु की पार्श्वभूमि बंगाल की है। अकाल जैसी आपदा के लिए सरकार की लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं मिली। यह जानकर पदचिन्ह गांव का एक धनिक महेंद्र अपनी सुस्वरूप पत्नी कल्याणी तथा इकलौती कन्या सुकुमारी को साथ लेकर अपनी विरासत स्वरूप घर त्याग कर बाहर निकल पड़ा। सुकुमारी एक साल की है। उसके लिए दूध की तलाश में महेंद्र, कल्याणी और सुकुमारी को एकझ कुटिया में छोड़ निकल पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर कुछ डाकुओं ने मां बेटी का अपहरण कर लिया। उन्हें मार कर खाने का डाकुओं का इरादा था। उन डाकुओं की आपसी बातचीत अपने नायक की क्रूर हत्या और नरमांस भक्षण की नृशंसता देखकर दिल दहल जाता है। ऐसे हालात बंकिम चंद्र के समय निश्चित ही रहे होंगे। इस बात का अंदाजा कोई भी वाचक आसानी से लगा सकता है। परंतु, एक के बाद एक संकट को कमजोर दिल वाला जब विरोध नहीं कर पाता, तब यह केवल शारीरिक रूप से जीवित रहता है लेकिन मन से वह मर जाता है।

मुद्दा

भूपेन्द्र भारतीय

कृषि कार्य के समय रास्तों को लेकर होने वाले विवाद

इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। फसल बुआई व कटाई भारतीय ग्रामीण व कृषि संस्कृति में एक उत्सव व त्यौहार की तरह होता है लेकिन देखने में आता है कि वर्तमान में लोग छोटी छोटी बातों पर विवाद कर लेते हैं और वह भी कृषि कार्य के लिए एक खेत में से दूसरे खेत में जाने जैसी सामान्य गतिविधि में विवाद होता है। इस समय में प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के समय एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए मार्गों(रास्तों) को लेकर अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच रास्ते के मामले में विवाद बढ़ जाते हैं। यह देखने में आया है कि ग्रामीण भारत में हर पांच आपराधिक घटनाओं में से तीन आपराधिक घटनाएं रास्ते व कृषि भूमि के विवाद से संबंधित होती है। लेकिन हर अपराध को पुलिस व न्यायपालिका सामान्य घटना मानकर उसपर कार्यवाही करते है ना की मूल समस्या में जाकर न्याय करें व सरकार को उचित दिशानिर्देश भी दे। यहां एक समस्या यह भी है कि कृषि, कृषि व्यवस्था व राजस्व जैसे विषय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में आते हैं। इसलिए हर राज्य ने इन विषयों में अपने अपने अनुसार विधि बनाई हुई है। लेकिन यह समस्या भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से देखी जा सकती हैं। ये विवाद बहुत बार खूनी संघर्ष का रूप ले लेते हैं और कितनी ही हत्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों व जमीन के विवाद को लेकर हो जाती है।

अधिकांश राज्यों व अपराध के राष्ट्रीय आंकड़ों में रास्तों के मामलों में छोटे मोटे विवादों की तो कोई निश्चित गिनती ही नहीं है। शुरुआत में रास्तों से संबंधित विवाद सामान्य दिखते हैं लेकिन आगे चलकर ये विवाद बड़ी घटना का रूप ले लेते हैं और फिर अंत में अपराध बन जाते हैं। ऐसे में राजस्व विभाग व कृषि मामलों से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस मामले में व फसल बुआई व कटाई के समय ऐसे मामलों को

लेकर विशेष सतर्कता व ध्यान देना चाहिए। यदि उचित हो तो राज्य सरकारों व राजस्व विभाग को भू- राजस्व संहिता में भी उचित संशोधन व बदलाव करना चाहिए। कृषि कार्य के दौरान किसान व कृषि मशीनों के स्वतंत्र आवागमन पर एक राष्ट्रीय आदेश व नीति निर्धारित की जाना चाहिए। क्योंकि यह एक गंभीर व बड़ी ग्रामीण जनता के अधिकारों से जुड़ी समस्या है। यह समस्या सिर्फ एक राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कृषि प्रधान राज्यों में भी बड़े स्तर पर घटित होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के विवादों के समाधान के लिए कोई एक स्पष्ट नीति व विधान नहीं है। यहां तक कि राष्ट्रीय अपराध आंकड़ों में भी इस तरह के अपराध व घटना पर कोई स्पष्ट शोध नहीं हुआ है। यहां तक कि विधानसभाओं व संसद में भी इस तरह की समस्या पर कोई गंभीर चर्चा करते हुए नहीं देखा गया है।

वैसे अधिकांश राज्यों ने भू राजस्व संहिता कानूनों में जरूर रास्तों के संबंध में प्रावधान किए हैं लेकिन धरातल पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। राजस्व के बड़े अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही जाते हैं तथा इस तरह के विवाद पर अपना निर्णय व आदेश पटवारी की रिपोर्ट पर ही देते हैं जो कि अधिकांश समय संदिग्ध रहती हैं। वहीं वरिष्ठ व बड़े राजस्व अधिकारी इस समस्या पर कम ही ध्यान दे पाते है क्योंकि उन्हें अधिकांश समय राजनीतिक दलों की सरकारी प्राथमिकताओं वाले कार्य पहले करने होते हैं। एक विडंबना यह भी है कि सरकारें इस समस्या को न्यायालय का कार्य मानती है वहीं व्यवहार व दंड न्यायालय इस तरह के विवादों को राजस्व न्यायालय के पास भेज देती है। जिससे कि पीड़ित किसान सरकारों, राजस्व विभाग व न्यायालयों के चक्कर काटते काटते इतना पीड़ित व परेशान हो जाता है कि वह अंत में बड़ा अपराध तक कर बैठता है। जिसमें हत्या, आपराधिक मानववध, आत्महत्या, गंभीर अपराध आदि जैसी अपराध की घटनाएं हो जाती है।

पंचायती राज आने के बाद ग्रामीण भारत में रास्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए पंचायत स्तर पर कुछ समितियां बनाई जाती है लेकिन उनकी बात का प्रभाव इस तरह के पक्षकारों पर नहीं के बराबर रहता है। ये समितियां व ग्रामीण न्यायालय अब तक गाँवों में प्रभावी व शक्तिशाली नहीं है। जिससे कि शहरी क्षेत्र में पीड़ितों को जाना पड़ता है और वहां तक जाते जाते न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है।

अब जबकि हमने विकसित भारत @2047 का लक्ष्य निश्चित कर लिया है जो कि ग्रामीण भारत में शांति स्थापित करें बगैर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं माना जाऐगा। ऐसे में भारतीय ग्रामीण समाज व सरकारों को भी इस गंभीर विषय पर भी विशेष ध्यान देना होगा तथा इस तरह के विवादों के समाधान के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति व विधान बनाना होगा। ग्रामीण व सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह भी बहुत जरूरी कार्य है। कृषक समाज को भी आपसी सहयोग व प्रेम बनाये रखना चाहिए तथा इस तरह के छोटे मामलों में धन व समय खराब नहीं करना चाहिए। जिससे कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में शांति से कृषि कार्य हो व ग्रामीण समाज शांतिपूर्वक रहे। ऐसे विवाद कम होने से पुलिस विभाग व न्यायपालिका पर भी कार्य का दबाव कम होगा। वहीं विकसित ग्रामीण भारत की गौरवशाली परंपरा व संस्कृति पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगी।

पर्यावरण

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक स्तम्भकार हैं।

मार्च में ही हीट वेव की चेतावनी

देश में जलवायु परिवर्तन के अज़ब गज़ब नज़ारे देखने को मिल रहे है। इस बार सर्दी का प्रकोप कम ही देखने को मिला, मगर मौसम विभाग की माने तो इस बार माह मार्च से ही लोगों को गर्मी की गर्माहट से दो दो हाथ करना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 2025 के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। आमतौर पर हीट वेव का ये दौर अप्रैल खत्म होने के साथ शुरू होकर मई के महीने में अपनी तेजी पर होता है। लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आईएमडी की चेतावनी है कि इस बार मार्च का तापमान सारे पिछले रिकार्ड ध्वस्त कर सकता है। हीट वेव की एडवाइजरी में हाइड्रेशन पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। अगर कहीं जा रहे हैं तो हमेशा अपने साथ पानी रखें, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। मौसम विभाग का अलर्ट डराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक, मार्च से मई के दौरान देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक हीटवेव वाले दिन रहने की संभावना है। इसका अधिकतर असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में देखने को मिलेगा। मार्च महीने के शुरुआती दौर में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। आमतौर पर इन दिनों में गुलाबी सर्दी रहती है, लेकिन मौसमी बदलाव ने सर्दी को जैसे गायब सा कर दिया है।

यह जलवायु बदलाव का नतीजा है की फरवरी समाप्त होते होते और मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी सिर चढ़कर बोलने लगी है। उत्तर भारत में पंखों के साथ कूलर और एयर कंडीशन चलने लगे है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च का महीना पूर्व के मकाबले सबसे गर्म महीना रहेगा। अपने 140 सालों के इतिहास में पहली बार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मार्च में चलने वाली गर्मी की लहर के लिए सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में गर्मी से सम्बंधित चेतावनियां भी शामिल है। वैसी ही जैसी भारी बारिश और चक्रवातों के सम्बन्ध में दी जाती हैं। तापमान में काफी वृद्धि होने से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है जिससे मलेरिया, वायरल, फीवर, खांसी, जुकाम, फ्लू, डायरिया ने पैर पसार लिए है। तापमान में भी घटत बढ़त होने लगा है। ऐसे में बहुत से लोग मौसम में परिवर्तन को झेल नहीं पाते और तबीयत बिगड़ जाती है। मौसम परिवर्तन और बीमारियों का चोली दामन का साथ है। विशेषकर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वे मौसमी बीमारियों का शिकार हो जाते है।

इस ऋतु में मौसम उच्च तापमान के कारण अधिक गर्म हो जाता है, जो कुछ क्षेत्रों में बिजली की आँख मिचोली के साथ पानी की आपूर्ति में कमी की वजह से सूखे का कारण बनता है। गर्म हवाएं और तापमान में

वृद्धि, दोनों ही इस ऋतु को बहुत अधिक गर्म बनाती है, जो मनुष्य और जंगली जानवरों दोनों के लिए बहुत अधिक परेशानी का निर्माण करता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग पानी की कमी, उच्च तापमान, सूखे आदि बहुत सी परेशानियों से बिजली और अन्य आरामदायक संसाधनों की कमी के कारण जूझते हैं।

मौसम विभाग का कहना है लोग अभी से खास सावधानियां बरते। बीमारियों से बचाव करें। गर्मियां भी मौसमी बीमारियों के साथ आती हैं। गर्मी में होने वाली गर्मी से थकावट, लू लगना, पानी की कमी, फूड पॉयजनिंग आम बीमारियां हैं। इस मौसम में हमें अपना ख्याल रखने की अधिक जरुरत होती है। अगर इस मौसम में आप जरा से भी चुके तो आपको कई बीमारियां घेर सकती है। यह एक ऐसा मौसम है जिसमें बीमारियां होने की आशंका अधिक होती है। मौसम का यह बदलाव मानव के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इससे बचने का एक मात्र उपाय सतर्कता और जागरूकता ही है। यह बीमारियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर कई बार आपके आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करती हैं। इनसे बचने के लिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक है।

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी से बचाव ही इस मौसम में बीमारियों से बचने का रास्ता है। इसके लिए पेय-पदार्थों का खूब सेवन करें। डॉक्टरों की सलाह है कि दिन में जब भी घर से निकले कुछ खा कर और पानी पी कर ही निकले खाली पेट बाहर ना जाएं। तेज धूप में, खासतौर से दोपहर में बेकाम घर से बाहर जाने से बचें। गर्भवती महिलाओं, हार्ट पेशेंट, 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोग, छोटे बच्चे और नवजात को हीटवेव से बचाना चाहिए द्धगर्मियों में हरे पत्ते वाली सब्जियां, विटामिन सी से युक्त रसीले फल और नींबू पानी लेना चाहिए। बेल का शरबत गर्मी के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। गर्मी के मौसम में जीरा-नमक डालकर छाछ पीना भी फायदेमंद होता है।

चैत्र नवरात्रि में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन

आमला । इस माह 30 मार्च से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्रि के मौके पर शहर के वार्ड क्रमांक 5 में शतचंडी महायज्ञ शुरू होने जा रहा है,इस दौरान यहां प्रतिदिन देवी भागवत का वाचन भी किया जाएगा।आयोजन समिति द्वारा बताया गया है कि कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है इस पूरे कार्यक्रम को वाराणसी के महंत स्वामी बलरामपुरी द्वारा संपन्न कराया जाएगा।

नर्मदा परिक्रमा करके दादा समर्थ गुरु का नगरामन

सुबह सवेरे सोहागपुर । नर्मदा मिशन के दादा समर्थ गुरु का आज शाम सैकड़ों नर्मदा परिक्रमा वासियों के नगरामन हुआ। आज रात नगर के विख्यात देनवा गार्डन में रात्रि विश्राम करेंगे। इधर पुलिस ने भी माकूल इंतजाम किए थे। उनके आगमन पर नागरिक अभिवादन कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि देवना गार्डन में यह दादा गुरु का दूसरी बार रात्रि विश्राम है।

अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई, लगातार अनुपस्थित रहने वाले प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

बैतूल। बैतूल एसपी निश्चल एन. झारिया ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर एक प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया है। रक्षित केंद्र बैतूल में तैनात प्रधान आरक्षक साहबलाल धुर्वे 244 दिनों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। विभागीय जांच में पाया गया कि धुर्वे ने मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64(4) का उल्लंघन किया। इस नियम के अनुसार हर पुलिसकर्मी को अनुशासन में रहना और विधिसंगत आदेशों का पालन करना जरुरी है। जांच के दौरान धुर्वे के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध हुए। एसपी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके सेवा अभिलेख से पता चला कि वे पहले भी कई बार अनुशासनहीनता का प्रदर्शन कर चुके हैं। एसपी झारिया ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल की साख बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्तव्य में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

न्यायाधीश और वकीलों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

बैतूल/आमला। आमला न्यायालय परिसर में वकीलों और न्यायाधीश का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में लगभग 70 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। संयोजक राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शिविर में न्यायाधीश वकील कोर्ट स्टाफ का प्रमुख रूप से ब्लड प्रेशर शुगर हिमोग्लोबिन व अन्य आवश्यक जांच शासकीय चिकित्सालय आमला के चिकित्सकों के सहयोग से किया गया। न्यायाधीश तपेश दुबे ने वकील और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिवेश में कार्य का अत्यधिक होना, समयावधि में प्रकरणों का निराकरण करना है। परिस्थिति अनुकूल न होने संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वकील न्यायाधीश और कोर्ट स्टाफ पर काम का बहुत अधिक दबाव रहता है, इसीलिए समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव आने और लोग अत्याधिक मोबाइल गैजेट्स का देर रात तक उपयोग करते है। नींद पूरी नहीं होने से भी लोग अत्याधिक बीमार हो रहे हैं। अत्यधिक मोबाइल का उपयोग करने से आंखों की रोशनी भी लगातार कम हो रही है। चिकित्सक के द्वारा न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे, राहुल निरंकारी, चारु व्यास, एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया सहित समस्त स्टाफ एवं वकीलों को परीक्षण कर स्वस्थ जीवन शैली के बारे में परामर्श भी दिया गया । वकील संघ के अध्यक्ष हिरामन नागपुरे, सचिव दिनेश सोनी भी मौजूद रहे।

जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध

बैतूल। पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 की धारा-3 के अनुसार कलेक्टर बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। विशेष परिस्थिति में अनुमति उपरांत की निजी नलकूप खनित किये जा सकेंगे। शासकीय, पेयजल प्रयोजन हेतु नलकूप खनन में प्रतिबंध शिथिल होगा। कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में आज 04 मार्च से निजी नलकूप पर प्रतिबंध लागू किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन अथवा अन्य कार्य किया जाता है, तो दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला आज

बैतूल। रोजगार कार्यालय, आईटीआई और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम के तहत जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आज 6 मार्च को प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने युवाओं से रोजगार मेले का लाभ लेने की अपील की है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 12 कंपनियां योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि शक्ति मोटर्स मुलतापी प्राइवेट लिमिटेड मुलताई में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, मैकेनिक, हेल्पर के 22 पदों के लिए योग्यता 8वीं से स्नातकोत्तर, आईटीआई डिप्लोमा होना अनिवार्य है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड बैतूल में बीमा अभिकर्ता के 50 पद तथा जेके बायो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के 20 पद के लिए योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार कुलोदय टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड दमन गुजरात में मशीन ऑपरेटर, मैकेनिक हेल्पर के 100 पदों, वर्धमान फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड बुदनी में मशीन ऑपरेटर, ट्रेनी वर्कर के 200 पद तथा ट्राईटेंड एंड प्राइवेट लिमिटेड बुधनी में मशीन ऑपरेटर, ट्रेनी वर्कर के 100 पदों के लिए योग्यता आठवीं, दसवीं, बारहवीं, आईटीआई होना अनिवार्य है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक सानंद औरंगाबाद में मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल उत्पादन विभाग में 500 पदों के लिए योग्यता डिप्लोमा, डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरी है।

बिजली की बढ़ती कीमतों के कारण लोग घरों की छत पर लगा रहे सोलर पैनल

488 घरों की छत पर लगे सोलर पैनल, बन रही बिजली

संजय द्विवेदी, बैतूल। बिजली की बढ़ती कीमतों के कारण लोग घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई है। जिससे भी लोगों का सोलर पैनल को लेकर रुझान बढ़ा है। यदि शहर की बात करते तो शहर में सोलर पैनल की मदद से हर माह करीब दो लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सोलर पैनल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने सरकार 78 हजार रुपए की सब्सिडी भी दे रही है। इससे योजना में लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। एक किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है, यानी माह में 120 से 150 यूनिट बिजली उत्पादन होती है। अगर किसी घर की औसत खपत 200 यूनिट प्रति माह है, तो 3 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने से पूरा बिजली बिल जीरो हो सकता है। घर में सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ता योजना के पोर्टल, बिजली कंपनी के ऐप, वेबसाइट या क्यूआर कोड स्कैन कर आवेदन कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर 30 हजार से 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है।

400 से अधिक घरों पर लगे सोलर पैनल -शहर में दक्षिण संभाग अंतर्गत पांच साल पहले बहुत कम सोलर पैनल लगे थे। लेकिन फरवरी 2024 में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आने के बाद अब तक शहर में घरों और कमर्शियल करीब 488 छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। इनमें 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर पैनलों की संख्या ज्यादा है। घरों में लगे सोलर पैनलों से प्रतिमाह 2 लाख यूनिट से अधिक का बिजली उत्पादन किया जा रहा है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। विद्युत कंपनी के मुताबिक आमतौर पर उपभोक्ता 3 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, जिससे वे न सिर्फ अपने घर की जरूरत पूरी कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर मुनाफा भी कमा रहे हैं।

कंपनी के पास 100 से अधिक आवेदन पेंडिंग - जिले में योजना में अब तक 488 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगवाए हैं, और घर बैठे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। बताया गया कि विद्युत वितरण कंपनी के पास योजना के तहत सोलर पैनल लगाने आवेदन अभी पेंडिंग हैं। सोलर पैनल लगाने विद्युत वितरण कंपनी में विधिवत आवेदन करना पड़ता है। जिसके बाद विद्युत कंपनी द्वारा उपभोक्ता को नेट मीटर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें सोलर पैनल से कितनी बिजली का उत्पादन हुआ और कितनी बिजली जलाई गई और कितनी बिजली शेष बची है। इसकी गणना रीडिंग में दर्ज होती है। जिसके बाद ही विद्युत कंपनी द्वारा बिजली बिल की गणना की जाती है। यदि उपभोक्ता कम बिजली जलाता है और अधिक बिजली का उत्पादन होता हैं तो बिलिंग में उपभोक्ता को फायदा पहुंचता है।

सरकारी विभागों में लग रहे सोलर पैनल - बिजली बिल में कमी करने के लिए अब सरकारी विभाग भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं। ज्यादातर विभागों ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं। इनमें कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, जिला अस्पताल, नगरपालिका, जेएच कॉलेज, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सरकारी भवन शामिल बताए जाते हैं। सोलर पैनल लगाए जाने के बाद इन विभागों में बिजली बिलों की कमी आई है। वहीं आम लोग भी बिजली बिल बचाने के लिए सोलर पैनल लगा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सरकार भी लोगों को बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी जैसी सुविधा मुहैया करा रही है।

इनका कहना है - पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन किए हैं। अभी तक करीब 488 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। सब्सिडी की वजह से भी लोग योजना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।

- बीएस बघेल, डीजीएम
दक्षिण संभाग बैतूल

बाजार से गायब हुए छोटे नोट और चिल्लर, आमजनों को हो रही परेशानी, व्यापारी संघ ने कहा सभी बैंकें उठाए कदम

आमला । चिल्लर लेकर आओ! वापस पैसे के बदले कोई सामान ले लो! दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से इन दिनों कुछ ऐसा ही ज्यादातर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बाजारों में छोटे नोट और चिल्लर का अचानक टोटा हो गया है, जिसके चलते ग्राहकों और दुकानदारों के बीच समस्याएं बन रही है, बाजारों से अचानक छोटे नोटों और चिल्लर के गायब होने से व्यापारी और ग्राहकों के बीच कई परेशानियां तो हो ही रही है, इसके अलावा कई लोग इसे साजिश भी बता रहे हैं इस दौरान लोगों ने कहा है कि कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर बाजारों से छोटे नोट और चिल्लर गायब कराई जा रही है। अब लोगों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अलग बात है किंतु बीते कुछ महीनो से इलाके में चिल्लर के चलते लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि कैशलेस लेनदेन अभी सभी लोगों के लिए आसान नहीं है जिससे परेशानियां ज्यादा हो रही है।

सबसे ज्यादा दिक्कत सब्जी बाजार में - इलाके में बीते कुछ समय से छोटे नोटों और चिल्लर का टोटा है, जिससे दिक्कतें तो है और यह भी सच है कि ज्यादातर लोग अब कैशलेस भी हो गए हैं। किंतु फिर भी छोटी-छोटी खरीदी के लिए लोगों को नगद व्यवहार ही करना पड़ता है, खासकर सब्जी बाजार एवं अन्य कई तरह की खरीदी के लिए नगद पैसों से ही लोग लेनदेन ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किंतु बाजार से जब

छोटे-छोटे नोट और चिल्लर गायब है, तो लोगों को परेशानियां ज्यादा हो रही है।

बुजुर्गों ने कहा नगद लेनदेन सुविधाजनक - इस मौके पर शहर के दीनानाथ पवार, लक्ष्मी पवार, रमाबाई यादव, कांताबाई ये सभी लोग पेंशनर है और पेंशन पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं, इनका कहना है कि नगद व्यवहार ही हम बुजुर्गों के लिए ज्यादा सुविधाजनक है। इस मौके पर लोगों ने बताया है कि चिल्लर नहीं होने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं छात्रा दिव्या, साक्षी, मानसी ने बताया कि इन लोगों को अभी भी कैशलेस से ज्यादा नगद लेनदेन ही अच्छा लगता है, हालांकि कैशलेस लेनदेन को भी कई लोग ज्यादा बेहतर मान रहे हैं अब जो भी हो लेकिन इन दिनों चिल्लर की कमी से लोग खासे परेशान तो हैं।

व्यापारी संघ ने कहा बैंके आगे आए - इधर इलाके में छोटे नोट और चिल्लर की कमी के बाद स्थानीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय साहू ने कहा कि बीते कुछ महीनों से चिल्लर पैसे की किल्लत बन गई है, सभी जगह और सभी के द्वारा कैशलेस अभी सुविधाजनक नहीं है, ऐसे में हम बैंकों से मांग करते हैं कि शहर की सभी बैंके किसी भी सुविधाजनक माध्यम से व्यापारी और आम लोगों तक छोटे नोट पहुंचने की व्यवस्था बनाएं।

इनका कहना है - हमारे पास चिल्लर की कोई कमी नहीं है किंतु जो भी बैंक से पैसे निकालने आते हैं सभी बड़े नोट ही मांगते हैं हमारे पास सभी तरह के छोटे बड़े नोट चिल्लर उपलब्ध है।जिन लोगों का हमारे बैंक में खाता है वह सुविधा अनुसार बैंक से चिल्लर ले सकता है।

राकेश झारे मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक रेलवे शाखा आमला

बेअरलॉकर उद्योग ने हरमवडी और हीरापुर के बच्चों को दी 40 सेट फर्नीचर की सौगात

देवास/मोहन वर्मा । अपने सामाजिक दायित्वों के तहत बेअरलॉकर उद्योग ने घाट नीचे स्थित पुंजापुरा के नजदीक हरमवडी के प्राथमिक स्कूल में 15 सेट तथा हीरापुर की एकीकृत शाला में पढ़ने वाले वंचित वर्ग के बच्चों को 25 सेट फ़र्नीचर की सौगात दी । बेअरलॉकर उद्योग के सीएसआर प्रबंधक प्रवीण शर्मा तथा सीएसआर सहयोगी एक्ट ईव फाउंडेशन अध्यक्ष मोहन वर्मा ने बताया कि उद्योग द्वारा अब तक विभिन्न स्कूलों में एक हजार से अधिक फ़र्नीचर भेंट किए जा चुके हैं जिनका लाभ तीन हजार से ज्यादा बच्चे ले पा रहे हैं और जरुरतमंद बच्चों को स्कूल फ़र्नीचर उपलब्ध करवाने का यह अभियान सतत जारी रहेगा ।

कार्यक्रम में अतिथि रूप में पूर्व जनपद सदस्य नंदु रावत उपस्थित थे। रावत ने कहा घाट नीचे जिले के अंतिम छोर के गांवों के बच्चों के लिये फ़र्नीचर पाना बहुत बड़ी खुशी है । हम क्षेत्रवासियों की और से बेअरलॉकर उद्योग तथा सामाजिक संस्था एक्ट ईव फाउंडेशन के आभारी हैं कि उन्होनें वंचित वर्ग के बच्चों की सुध ली। कार्यक्रम में विजय सांगते,किशन सिंह कुशवाह, विजय माली,देवेन्द्र राठौर,हजारी देवड़ा जयराम पटेल, देवी सिंह रावत,कांशीराम रावत,अर्जुन सिंह, सरपंच मोहन बामनिया,रंजीत निगवाल,मोहन डावर, धारा मोरे उपस्थित थे स्कूल प्रबंधन ने बेअरलॉकर उद्योग और एक्ट ईव फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया ।

महाराणा प्रताप ने देश और समाज के लिए जीने की दी प्रेरणा : नरेन्द्र सिंह तोमर

विधानसभा अध्यक्ष ने मुलताई के बाड़ेगांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण

बैतूल। विधानसभा अध्यक्ष मध्यप्रदेश शासन नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को तहसील मूलताई के ग्राम बाडेगांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती और डॉ भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, उपाध्याय जन अभियान परिषद मोहन नागर, पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह, विधायक हेमंत खंडेलवाल, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, सुधाकर पवार, सुरेन्द्र सिंह सोलंकी, जसपाल सिंह सिसोदिया, अनिल कुशवाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि आज बाड़ेगांव की इस पावन भूमि पर वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए जन-जन में पूजे जाते हैं। महाराणा प्रताप जी की वीरता,स्वाभिमान, देशभक्ति की भावना, माता और बहनों के सत्तित्व की रक्षा के कार्य सतत समाज को प्रेरित करते रहेंगे। महाराणा प्रताप जी राजपूत ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की रक्षा के लिए मुगल आक्रांताओं से लड़े। जिसमें समाज का हर वर्ग भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ युद्ध में सहभागी बना। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम इतना अद्भुत था कि मुगल शासक अकबर ने उनसे सीधे टकराने का कभी साहस नहीं किया। महाराणा प्रताप ने खुद की बजाय देश और समाज के लिए जीकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी हैं। उन्होंने सभी से महाराणा प्रताप जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतरने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जसपाल सिंह सिसोदिया, अनिल कुशवाहा और विधायक हेमंत खंडेलवाल को धन्यवाद दिया।

केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं। उन्होंने मुगल आक्रांताओं के प्रवेश के कालखंड में देश की रक्षा करने का काम किया हैं। महाराणा प्रताप द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने की शिक्षा आज भी हमें अनीति और अनाचार के विरोध लडने के लिए प्रेरित करती है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया हैं। महाराणा प्रताप समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि थे। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा नवीन पीढ़ी को राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की शिक्षा देती रहेगा। विधायक डॉ योगेश पंडाग्रे ने कहा कि महाराणा प्रताप जी वीरता, समर्पण स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय के प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया और उनका वीरता से प्रतिकार किया। आमला में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विधायक श्री देशमुख ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। विधायक घोड़ाडोंगरी गंगाबाई उईके ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप जी की वीरता पर प्रकाश डाला और सभी से उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।

आमला एसडीएम ने ग्राम पंचायत में आयोजित शिविरों का किया औचक निरीक्षण

फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने एसडीएम ने दिए निर्देश

बैतूल/आमला। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने समस्त एसडीएम को अपने क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री सहित राजस्व प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आमला एसडीएम शैलेंद्र बडोनिया ने बुधवार को आमला जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में आयोजित फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों के किए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी को देखा। उन्होंने किसानों से चर्चा कर फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों को स्वावलंबी बनाने अनेकों महत्वावकांक्षी योजनाओं चलाई जा रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के प्रकरणों की समीक्षा कर कम प्रगति वाले ग्राम पंचायतों को लक्ष्य पूर्ण किए जाने के निर्देश भी दिए।

जानकारी के अनुसार एसडीएम श्री बडोनिया ग्राम पंचायत तोरणवाड़ा, ग्राम पंचायत बोरीखुर्द, ग्राम पंचायत जामदेहीखुर्द, ग्राम पंचायत बारंगवाड़ी पहुंचे। उन्होंने पटवारियों को फार्मर रजिस्ट्री के पोर्टल पर पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के लंबित प्रकरणों पर एसडीएम श्री बडोनिया ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आधार खसरा लिंक, ई-केवाईसी के भी लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, जिला पंचायत सदस्य महेश मर्सकोले सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित थे।

गौवंश तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

बैतूल। सांईखेड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर तीन नग मवेशियों को गौशाला पहुंचाया। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गौवंश को अवैध रूप से महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहा है। थाना सांईखेड़ा पुलिस ने ग्राम रावा के आगे पारसडोह जाने वाली सडक़ पर बिसनूर-रावा तिराहे के पास रात्रि लगभग 2 बजे घेराबंदी की। पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को तीन बैलों को रस्सी से बांधकर लकड़ी से क्रूरतापूर्वक मारते हुए भूखी-प्यासी हालत में महाराष्ट्र की ओर ले जाते हुए देखा। पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

जनता को भिखारी बताने वाले सत्ता में बैठे मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें: कांग्रेस की मांग

देवास । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री पटवारी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई देवास में जिले के नियुक्त प्रवक्ता अमित चौरसिया ने बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी बताए जाने की उनकी ओछी मानसिकता घृणानात्मक निष्कृष्ट सोच और भाजपा सरकार की महिला, किसान ,युवा और जन विरोधी नीतियों के विरोध में मीडिया के समक्ष जनता की आवाज को बुलंद करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी द्वारा लिया गया है ।

श्री चौरसिया ने कहा कि भा ज पा सरकार ने 20 वर्षों में प्रदेश को बदहाली असुरक्षा और अपमान के गर्त में धकेल दिया है अब तो हालत यह हो गए है की जनता को भगवान बताकर वोट बटोरने वाली भाजपा

सरकार महिलाओं बुजुर्गों किसानों युवाओं विद्यार्थियों और दिव्यांग जनों को भिखारी बता रही है। सत्ता के नशे में चूर पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा यह कहना कि एक फूल माला लेकर साथ में मांग का आवेदन लेकर भिखारी की तरह आ जाते हैं यह उनके अहंकार को दर्शाता है यह सीधे-सीधे जनता का अपमान है प्रजातंत्र में इस तरह की भाषा और व्यवहार का कोई स्थान नहीं है । कांग्रेस ने पूछा है की उनकी बात पर सरकार और मंत्री पटेल जवाब दे की प्रदेश के लोगों को युवाओं को महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय उनका अपमान क्यों कर रहे हैं।

इसी के साथ श्री चौरसिया ने कहा कि 6 तारीख को 12 बजे शहर जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया जाएगा 8 मार्च को जिला मुख्यालय पर धरना देकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर मंत्री पहलाद पटेल से इस्तीफा की मांग की जाएगी 10 मार्च को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उमंग सिंगार हेमंत कटारे प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान की मौजूदगी में किसान कांग्रेस द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन आयोजित किया गया है 11 से 15 मार्च तक कांग्रेस के मोर्चा संगठन विभागों के अध्यक्षों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभागीय मंत्रियों से विभाग संबंधी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, अशोक पटेल शौकत हुसैन ,भगवान सिंह, चावड़ा, सुधीर शर्मा, चंद्रपाल सिंह सोलंकी ,प्रमोद सुमन, इम्तियाज शेख़ भल्लू, राहुल पवार, पंकज वर्मा दिग्विजय सिंह झाला उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

यातायात सुधार की मुहिम जारी

तेजाजी नगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में हटाये गए अतिक्रमण

इन्दौर (निप्र)। इंदौर में यातायात सुधार के लिए कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में लगातार मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत सड़कों और फुटपाथ पर सामग्री रख कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण हटाये जा रहे है। इसी सिलसिले में आज नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा झोन क्रमांक 13 में कार्रवाई की गई। बताया गया कि झोन क्रमांक 13 के अन्तर्गत तेजाजी नगर चौराहे क्षेत्र में फुटपाथ पर अवैध रूप से बने 27 टीन शेड हटाये गये। अन्य अतिक्रमण भी हटाये गए। उक्त कार्यवाही में एसडीएम श्रीमती प्रियंका चौरसिया एवं जोनल अधिकारी अंकेश बिरथरिया आदि उपस्थित थे। रिमूवल की टीम व यातायात बल द्वारा यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया। उक्त कार्यवाही में 19 हजार रुपये की चालानी कार्यवाही की गई।

विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम

कान-नाक-गला की देखरेख के संबंध में किया गया लोगों को जागरूक

इन्दौर (निप्र)। विश्व श्रवण दिवस के अवसर पर ईएनटी विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न संस्थाओं पर पदस्थ मेडिकल ऑफिसर एवं नर्सिंग ऑफिसर को कान-नाक-गला की देखरेख कैसे करें, इस हेतु जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इस अवसर पर खण्ड स्तर पर भी जन सेवा हेतु शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत पदस्थ मोबाइल हेल्थ दल द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही आम जन को सामुदायिक स्तर पर इस हेतु जागरूक भी किया गया कि कान के रिसाव होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें, कान को डॉक्टर से ही साफ करवाये, स्वयं या अन्य किसी से नहीं, अगर बार-बार कान से रिसाव हो रहा है, तो हो सकता है कान की हड्डी गल रही है या कोई अन्य वस्तु या चीज कान में फंसी हुई है। इसके अलावा अगर बच्चा जन्म से मूक बधिर है तो शासन के माध्यम से 05 वर्ष तक ऐसे बच्चों का आरबीएस के तहत बाल श्रवण योजना से निःशुल्क उपचार करवाया जाये, जिससे वह सुन व बोल सकें।

स्वच्छता में यूँ ही शिखर पर नहीं है इंदौर

इन्दौर (निप्र)। बीते कई वर्षों से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। यहाँ नागरिकों में स्वच्छता के लिए अभूतपूर्व चेतना विकसित है। वहीं नगर निगम प्रशासन भी स्वच्छता के मापदंडों को बनाए रखने के लिए सतत् प्रयास करता है। इंदौर शहर की सड़कें ही नहीं अपितु विभिन्न कॉलोनियों की बैकलाइन भी स्वच्छ और सुंदर बनायी गई है। आम तौर पर कॉलोनियों की बैकलाइन में गंदगी देखने को मिलती है, लेकिन इंदौर के वार्ड क्रमांक 43 श्रीनगर एक्सटेंशन की आदर्श बैकलाइन में साइकिलिंग, कैरम, बैडमिंटन के साथ ही अन्य खेल गतिविधियाँ की जा सकती है। गत दिवस महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने यहाँ की आदर्श बैकलाइन में साइकिलिंग तथाकैरमआदि का खेलों में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर महापौर परिषद सदस्य श्री अश्विनी शुक्ल, श्री राजेश उदावत, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती सुनीता दिनेश सोनगरा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहें।

वित्तीय भार को वहन किये जाने हेतु कर वसूली प्रारंभ की जाये

सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करना सुनिश्चित करें

शिविर आयोजित कर बनाये जायें आयुष्मान कार्ड एवं आधार कार्ड, जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

खण्डवा (निप्र)। सी.एम. हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का गंभीरता से एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि गेहूँ एवं चना उपार्जन का कार्य प्रारंभ होने वाला है। गेहूँ एवं चना उपार्जन के लिए खरीदी केन्द्र चिन्हांकित शासकीय एवं अशासकीय वेयर हाऊस पर ही बनाये जायें , ताकि उपज के परिवहन का अतिरिक्त व्यय ना हो। उन्होंने कहा कि अक्रियाशील सहकारी समितियों को चिन्हांकित कर उन्हें विधिवत रूप से बंद कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बैठक में उन्होंने वैकल्पिक रिंग रोड निर्माण हेतु ग्राम छोटी छैगांव देवी से डूल्हार तक की लोक निर्माण विभाग की सड़कों के साइड शोल्डर भरकर चौड़ीकरण करने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन योजना को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु वित्तीय भार वहन किए जाने के लिए संबंधित प्रत्येक ग्राम में निर्धारित कर वसूली प्रारंभ की जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि रबी की फसलों की कटाई आगामी दिनों तक पूर्ण हो जायेगी। किसानों की कृषि भूमि खाली हो जाने पर शेष रहे निर्माण कार्यों को चिन्हांकित कर पूर्ण कराया

जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल में स्थापित एनआरसी केन्द्र की मरम्मत करें या जर्जर घोषित कर डिस्मेंटल करने की कार्यवाही करें।

यदि डिस्मेंटल किया जाये तो उसे बनाने के लिए जगह भी चिन्हित कर ली जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने गौशालाओं के आसपास हो रहे अतिक्रमण की सूची बनाने के निर्देश उप संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी को दिए, ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके। साथ ही उन्होंने पशुओं के लिए चरवाई जमीन से भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों का कोषालय द्वारा संचालित आईएफएमआईएस पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक करायें, जिससे वेतन आहरण किया जा सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने लंबित अनुकम्पा एवं पेंशन प्रकरणों के निराकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2 माह में जो भी अधिकारी कर्मचारी रिटायर होने वाला हो उनके पेंशन प्रकरण की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि धरती आबा योजना में जिन गांवों को चिन्हांकित किया गया है उन गांवों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी योजनाओं के लिए शिविर आयोजित करें, ताकि हितग्राही योजनाओं का लाभ ले सकें।

उन्होंने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित गांवों में समग्र आईडी, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, प्रोफाइल पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने खालवा, पुनासा, बलड़ी, पंधाना में आधार कार्ड बनाने हेतु शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु भी निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ. गौड़ा ने आँचल अभियान के तहत सेम एवं मेम बच्चों की जानकारी ली और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि सेम एवं मेम बच्चों की सूची बनाई जाये जिसमें उल्लेख किया जाये कि किस व्यक्ति द्वारा उन्हें गोद लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा की ऐसे व्यक्ति जो बच्चों को गोद ले रहे हैं उन्हें फूड चार्ट भी वितरित किया जाये, जिससे उन्हें पता रहे कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु क्या आहार देना है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री के.आर. बड़ोले,एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण मौजूद थे।

गौ संरक्षण जन जागरण यात्रा

मनुष्य गौ माता का दौहन करके ,दूध देने तक वह चारा पानी देता है, अन्यथा वह घर से बाहर कर देता है संत बालकदास त्यागी जी महराज

हीरालाल गोलानी सोहागपुर । गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने एवं संरक्षण , संवर्धन के लिए गौ संरक्षण यात्रा ग्राम सांडिया से प्रारंभ हुई। उक्त यात्रा नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर समाप्त होगी।इस यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। पिपरिया से सोहागपुर विधानसभा के ग्राम करनपुर में समाजसेवी हरगोविंद पुरबिया उनके पुत्र सौरभ पुरबिया, जलज शर्मा, अनुराग शर्मा, मिथलेश ठाकुर, अरबिद पुरुविया, लालजी रधुवंशी आदि ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर बालक दास जी महाराज ने नागरिकों एवं किसानों से गौ संरक्षण से जोड़ने की अपील की। आपने किसानों को गौ आधारित खेती करने के लिए आव्हान किया । सोहागपुर मे नवीन बस स्टैंड पर भव्य स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है नवीन बस स्टैंड पर की दिनों से गौ माता को राष्ट्रीय माता देने को लेकर 18 फरवरी से रेवा सेवा भक्त मंडल के सदस्य

धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस स्टैंड पर यात्रा प्रमुख संत संत बालक दास जी त्यागी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज गौ माता सड़कों पर फिर रही है ।इससे गौ माता की दुर्दशा हो रही है ।मनुष्य गौ माता का दोहन कर रहा है ।जब वह दूध देती है ।तब तक तो उसे चारा पानी देते हैं ।जब वह दूध देना बंद कर देती है। तो उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं।स्वयं भगवान भी गौमाता की रक्षा के लिए समय-समय पर इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है ।तभी भारत विकसित और समृद्ध बनेगा,।गृहस्थ संत पंडित प्रकाश मुद्गल ने अपने उद्बोधन में कहा कि गो संवर्धन यात्रा पर निकले सभी यात्री साधुबाद के पात्र हैं ।उन्होंने बड़े ही शुभ कर्म का बीड़ा उठाया है ।आज गौमाता की रक्षा के साथ ही उसका

संवर्धन करना आवश्यक है ।हम गौ माता को माता इसलिए कहते हैं ।क्योंकि मां के दूध के बाद हम गौ माता के दूध से ही जीवन पालन पोषण करते हैं।कलयुग में इस माता की बहुत खराब स्थिति हो गई है ।इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के शिवकुमार पटेल ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं ।आज के समय में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करते हुए उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि हर नगरी निकाय में गौशाला संचालित की जाएगी जिसके लिए दोगुना फंड दिया जाएगा।रेवा सेवा भक्त मंडल के संयोजक बलराम पटेल यात्रा के संयोजक अभिषेक दुबे आदि ने भी सभा को संबोधित किया।यात्रा में जीवन जी दुबे,इंद्र कुमार दीवान ,बजरंग दल विभाग संयोजक श्रीकांत पटेल, जिला सुरक्षा प्रमुख आशीष पुरोहित, अधिवक्ता अखिलेश मालवीय, विक्रम रघुवंशी, रामचंद्र यादव ,युवा गुर्जर विकास समिति के अध्यक्ष बृजेश पटेल, मधुसूदन मुद्गल ,निपुण खंडेलवाल,अरूण चौरसिया आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उल्लेखनीय है इस गौ माता संरक्षण यात्रा में बैलगाड़ियां भी थीं।जिसका अलग ही आनंद था। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति रही।सभा का संचालन यश भार्गव ने किया। गौ संरक्षण यात्रा पलकमती नदी पुल से होकर मंगल भवन में रात्रि विश्राम किया।गौ संरक्षण यात्रा आज सेमरी हरचंद को प्रस्थान किया। इसी क्रम में शंभू दरबार प्लास परिसर में संत संत बालक दास जी महाराज का गृहस्थ संत पंडित प्रकाश मनमोहन मुद्गल ने आत्मीय स्वागत किया।

केंद्रीय मंत्री द्वारा वसुधैव कुटुंबकम के व्यावहारिक मॉडल की सराहना

इन्दौर (निप्र)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर गत दिवस इंदौर प्रवास के दौरान मानव चेतना विकास केंद्र पिवड़ाय का भ्रमण तथा अवलोकन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर ने यहाँ किए जा रहे प्रदूषण मुक्त उत्पादन, सम्बन्ध युक्त विश्वासपूर्वक जीने की मानवीय शिक्षा और व्यापार एवं लाभ-हानि मुक्त व श्रम मूल्य आधारित विनिमय कार्यों का अवलोकन किया। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी उन्होंने 30 परिवारों के प्रकल्प में परिवारों से चर्चा कर इसके प्रयास और परिणामों को सराहना की। श्रीमती ठाकुर ने सराहना करते हुए कहा कि यह वसुदेव कुटुम्बकम का व्यवहारिक मॉडल है। केंद्र के संस्थापक श्री अजय दायमा ने केंद्र में हो रही शिक्षा की वस्तु, प्रक्रिया और सफलताओं का अध्ययन करने और कराने का आग्रह किया और इसमें केंद्र की पूरकता व सहयोग के लिए आश्वस्त किया। केंद्र में संचालित सेवक मुक्त 160 गिर गाय की गौशाला का भ्रमण किया। इस दौरान गौशाला का नेतृत्व कर रही योग्या दीदी ने गौशाला परिवार की आवश्यकता और खेती में पूरकता को बड़ी ही सहजता के साथ स्पष्ट किया। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर ने गौशाला में गाय के 30 लीटर दूध से एक किलो घी बनने की प्रक्रिया को देखा और इसकी गुणवत्ता की प्रशंसा की। परंपरा के अच्छे कार्यों, श्रम शीलता व संस्कारों को बचाये रखते हुए परिवार के सदस्यों का तालमेल पूर्वक जीने में केंद्र के प्रयास अनुकरणीय है। शिक्षा और खेती से जुड़े विद्वान तथा मंत्रीगण भी इस प्रकल्प को अपने महत्वूपर्ण योगदान देंगे।

पार्षद कालरा जाति प्रमाणपत्र केस में 17 मार्च को सुनवाई

छानबीन समिति का कलेक्टर ऑफिस में दस्तावेज होने से इनकार, हाईकोर्ट ने निर्णय लेने दिया अंतिम अवसर

इंदौर, निप्र। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के जाति प्रमाणपत्र के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें छानबीन समिति की ओर से बताया गया कि उनके जाति संबंधी प्रमाणपत्र कलेक्टोरेट में नहीं मिले हैं। इस बीच समिति अध्यक्ष अजीत केसरी भी 28 को सेवानिवृत हो गए। अभी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते कोर्ट ने 17 मार्च तक निर्णय लेने का अंतिम अवसर दिया है।

4 फरवरी को अजीत केसरी (प्रमुख सचिव पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग), सौरभ कुमार सुमन (पिछड़ा और अल्पसंख्यक विभाग कमिश्नर, घनश्याम धनगर (एसडीएम जूनी इंदौर) ,वार्ड 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा सहित अन्य को हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया था। दो दिन बाद सभी ने कोर्ट से माफी मांगते हुए 1 हफ्ते में निर्णय लेने की गुहार लगाते हुए वारंट वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने 17 फरवरी तक की मोहलत दी थी। 17 फरवरी को फिर कुछ दिन की मोहलत मांगी गई तो कोर्ट ने 3 मार्च को सुनवाई तय की।

आज सुनवाई में समिति की ओर से स्पष्ट किया गया कि कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्र के मुताबिक कमलेश कालरा के जाति से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। समिति अध्यक्ष अजीत केसरी 28 को सेवानिवृत हो गए हैं, इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाए। नए अध्यक्ष एक-दो दिनों में चार्ज ले लेंगे। इस पर कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए अगली तारीख 17 मार्च रखी है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुनील यादव की याचिका पर वारंट जारी हुआ था। कालरा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने की शिकायत है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मनीष यादव और करण बैरागी ने तर्क रखे कि कोर्ट के आदेश के 6 माह बाद भी पार्षद कालरा के जाति प्रमाण पत्र की जांच में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। इसमें छानबीन समिति लंबे समय से जांच कर रही है लेकिन सारे तथ्य आ जाने के बाद भी निर्णय नहीं कर रही है।

आईआईटी इंदौर में बन रहा है नया हेल्थ प्लेटफॉर्म चरक डीटी

आईआईटी के 15 स्टार्टअप्स को मिली 5 करोड़ रुपये की फंडिंग

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह और सांसद श्री शंकर लालवानी ने सौंपे पत्र

इन्दौर (निप्र)। पैरालिसिस, उम्र या अन्य किसी कारण से चलने-फिरने में असमर्थ लोग भी चल सकेंगे। ये अनोखा वियरेबल सॉल्यूशन एक स्टार्टअप नोवा वॉक ने बनाया है जिसे आईआईटी इंदौर ने इनक्यूबेट किया है। साथ ही किसी भी भाषा में डॉक्टर से बात करने के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशन भी बनाया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अल्ट्रासाउंड रोबोट की मदद से सोनोग्राफी करना आसान हो गया है और सुटकेस में आ जाने वाली पोर्टेबल ब्लड टेस्टिंग यूनिट भी अब मौजूद है। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में ऐसे 15 स्टार्टअप को फंडिंग दी गई जो हेल्थ केयर सेक्टर में अनूठे प्रयास कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह एवं इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को फंडिंग का लेटर दिया। 15 स्टार्टअप्स को 5 करोड़ रुपये की फंडिंग दी गई है और ये राशि प्रत्येक स्टार्टअप के लिए बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जा सकती है। इन 15 में से कुछ स्टार्टअप आईआईटी के प्रोफेसर्स ने शुरू किए हैं तो कुछ भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने बनाए हैं, वहीं कुछ स्टार्टअप्स डॉक्टर और इंजीनियर्स ने मिलकर बनाए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब डॉक्टर्स, इंजीनियर का काम कर रहे हैं और कई इंजीनियर, डॉक्टर के मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से यह संभव हुआ है और नई शिक्षा नीति 2020 के कारण बहुत जल्द छात्र विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकेंगे। वहीं इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि आईआईटी इंदौर ने ऐसे स्टार्टअप्स की मदद की है जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। आज से 10-20 साल पहले जिन बीमारियों का इलाज असंभव लगता था वह आज स्टार्टअप्स ने संभव कर दिखाया है।

इन स्टार्टअप्स की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च स्तरीय हेल्थ केयर सुविधा पहुंचना संभव है। इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी श्री अभय करंदीकर, आईआईटी इंदौर के डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास जोशी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की हेड डॉ. एकता कपूर मौजूद थीं।

सीएसआर के लिए बैठक संपन्न

शाजापुर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ श्री संतोष टैगोर की अध्यक्षता में आज जिले में कार्यरत विभिन्न कंपनियों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किये जाने वाले कार्यों के चयन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एमपीएनआरईडी से श्री पंकज तिवारी, एनवीडीए से श्री एसएस परिहार, पावरग्रिड से श्री कृष्णनंदन तिवारी, प्रभारी सीएमएचओ डॉ. तेजपाल सिंह जादोन, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विवेक दुबे, आरईएस कार्यपालन यंत्री श्री अभिषेक यादव, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री विजय सिंह चौहान, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान, जनपद पंचायत सीईओ मो. बड़ोदिया श्री एआर सिसोदिया, एनआरएलएम से श्री मनोज जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राइट क्लिक

कमोबेश सभी मानक भाषाएं बोलियों को 'खा' रही हैं, पर इलाज क्या?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा और केन्द्र सरकार से अपनी राजनीतिक लड़ाई में जिस तरह हिंदी को खलनायक बनाने की कोशिश की है, उसके पीछे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटों की गोलबंदी तो है ही साथ में यह आरोप भी है हिंदी उत्तर भारत में अपनी पच्चीस बोलियों को खा गई। इस आरोप में आंशिक सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे कारण वो नहीं है, जो स्टालिन अपने सियासी चश्मे से गिना रहे हैं। आज अगर मानक हिंदी अपनी उपभाषाओं और बोलियों पर हावी हो रही है तो इसके पीछे बोलियों के संहार की मंशा न होकर मानक हिंदी भाषा का व्यावहारिक कारणों से बढ़ता इस्तेमाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 96.71 फीसदी आबादी भारतीय मानक भाषाओं का प्रयोग करती हैं। बोलियों का विलुप्त अथवा धीरे-धीरे चलन से बाहर होते जाना, यह समस्या अकेले हिंदी के साथ ही नहीं है बल्कि उन सभी संविधान मान्य 22 भारतीय भाषाओं के साथ है, जो अब अपने-अपने राज्यों की राजभाषाएं भी हैं, जिसमे खुद स्टालिन की मातृभाषा तमिल भी शामिल है। मानक हिंदी के बढ़ते चलन के कारण हिंदी की 18 बोलियों का दायरा सिकुड़ जरूर रहा है, लेकिन यह कहना कि हिंदी सुनियोजित तरीके से उनको 'खा' रही है, अपने आप में कुत्सित भाव लिए हुए है। स्टालिन को हिंदी के बारे में इतनी दुराग्रहपूर्ण गहरी जानकारी भी किसी ने दी ही होगी। अपने केन्द्र पर सियासी वार में स्टालिन ने दावा किया कि यूपी बिहार कभी हिंदी क्षेत्र नहीं थे तथा बीती एक सदी में जबरन हिंदी थोपने से उत्तर भारत की 25 भाषाएं समाप्त हो गईं। एक्स पर अपनी पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि हिंदी के कारण भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी, और कई सारी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए हांफ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने स्टालिन के इस बयान को 'मूर्खतापूर्ण' कहा है। भाषा विज्ञान के अनुसार यूपी की 'पूर्वी हिंदी' और बिहारी की 'बिहारी हिंदी' मानक हिंदी से थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन वह हिंदी क्षेत्र का भाग नहीं है, यह सरासर असत्य है।

अलबत्ता स्टालिन की पोस्ट में यह चिंता जरूर विचारणीय है कि हिंदी सहित सभी मानक भारतीय भाषाओं के अतिक्रमण से उनकी बोलियां और उपभाषाएं अपना वजूद कैसे बचाएं? खासकर वो बोलियां जो कभी मान्य भाषाएं ही थीं, लेकिन कालांतर में बोलियां बन कर रह गईं। जाने माने पत्रकार पी. साईनाथ का कहना है कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी जैसी भाषाओ को बोलियां कहना ही गलत है। हिंदी की तरह मानक कन्नड़ के कारण वास्तव में मान्य भाषाएं ही हैं, लेकिन अब मानक भाषाओं की दबंगई के आगे बोलियां कहलाने लगी हैं, प्रचलन से या तो बाहर होती जा रही है या फिर उनका दायरा ग्रामीण क्षेत्रों तक सिमटता जा रहा है। जहां तक आधुनिक और मानक हिंदी की बात है तो इसका इतिहास ही करीब डेढ़ सौ साल पुराना है। इसे भी शुरू में खड़ी बोली ही कहा जाता था। हिंदी के भी विद्वानों के अनुसार हिंदी के भी पांच रूप हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनमें भी विभिन्न कारणों से पश्चिमी हिंदी ही पहले खड़ी बोली और आज की मानक हिंदी के रूप में स्थापित हो गई है। यही राजभाषा भी है और विदेशियों के लिए भी 'हिंदी' से तात्पर्य इसी मानक हिंदी से है। शिक्षण संस्थानों में भी यही हिंदी पढ़ाई जाती है। हालांकि इस मानक हिंदी का स्वरूप भी बदलता रहा है। यह हिंदी अपनी बोलियो से ही ऊर्जा प्राप्त करती है। साथ ही उसे अन्य भाषाओं से शब्द संपदा लेने से गुरेज नहीं है। लिहाजा इसकी पाचन शक्ति भी अंग्रेजी की तरह विराट है। यह हिंदी चाहे अनचाहे दूसरी भाषाओं से शब्द, तेवर और मुहावरे लेती जा रही है और खुद को समृद्ध करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि भाषा का यह आदान- प्रदान एकतरफा हो, अन्य भारतीय भाषाएं भी व्यावहारिक तकाजों की वजह से हिंदी से शब्द और मुहावरे आयात कर रही हैं। कई बार तो यह आरोप भी लगता है कि हिंदीतर भारतीय भाषाएं हिंदी के 'अतिक्रमण' से भी जूझ रही हैं। सच्चाई यही है कि आज आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारणों से भी हिंदी देश की सर्वाधिक स्वीकार्य भाषा स्वतः बनती जा रही है, जिसमें राजनीतिक पलीता लगाने की कोशिश बहुत ज्यादा सफल शायद ही हो। हिंदी की विराट पाचन शक्ति ही यदि अन्य भारतीय भाषाओं के पैरोकारों को भाषाभक्षी राक्षसी वृत्ति लग रही है तो यह उनका दृष्टि दोष है। आखिर 140 करोड़ के बहुभाषी, बहुजातीय और बहुसंस्कृति वाले देश में एक बहुमान्य संपर्क भाषा समय की मांग है। अगर प्रौद्योगिकी हमे भौतिक रूप से करीब ला रही है तो अभिव्यक्ति और परस्पर संवाद के स्तर पर भी एक ऐसी भाषा की नैसर्गिक दरकार है, जिसके जरिए भारत के नागरिक एक-दूसरे से जुड़ सके। यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि वह इसी जमीन, देशज भाव और प्रेरणा और सांस्कृतिक आग्रह और दबाव से उपजी भाषा है। स्टालिन अगर चाहें कि हिंदी की जगह अंग्रेजी ले ले या फिर तमिल को यह ताज सौंपना चाहें तो यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। क्योंकि संपर्क भाषा वही बन सकती है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग बोल और समझ सकते हों। निश्चय ही तमिल भाषा का अपना महत्व है, वह भी बहुद्देशीय भाषा है, लेकिन भारत में वह हिंदी का विकल्प नहीं हो सकती।

अब सवाल यह है कि क्या सचमुच हिंदी अपनी उन बोलियों को खा रही है, जो उसकी पूर्वज और काफी हद तक जन्मदात्रियां हैं। वर्तमान में हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। जो भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में आज भी चलन में हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जैसे-जैसे आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण बढ़ रहा है, बोलियों का साम्राज्य घट रहा है। बोलियां अब ग्रामीण क्षेत्रों तक सिमटती जा रही हैं। हालांकि उनमें भी साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन उसकी मान्यता और लोकप्रियता सीमित है। दरअसल पढ़-लिख जाने और घर में बोली के उपयोग पर शर्म महसूस होना, बोली में संवाद को पिछड़ा या गंवारूपन समझने की भ्रामक मान्यता के कारण जिन घरों में कुछ साल पहले तक स्थानीय बोली बोलने का चलन था, उनमें भी अब मानक हिंदी ही बोलने और लिखने का चलन है। मीडिया की मुख्य भाषा भी यही है। इसके लिए हिंदी दोषी नहीं है बल्कि आधुनिक और सभ्य कहलाने की हमारी अपनी बनाई परिभाषा है। अब तो यह हो गया है कि बच्चा स्कूल जाते ही धीरे-धीरे पहले अपनी मातृबोली को तिलांजलि देता है फिर अंग्रेजी रंग में रंगने की कोशिश करता है। इसके लिए दोषी बच्चों के मां-बाप भी हैं, जो खुद ही घरों में बोली में संवाद बंद कर चुके हैं। बोलियां व पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को तजने के पीछे सोच यही है कि जब हिंदी जानने से ही रोजगार नहीं मिलता तो बोली को जिंदा रखने से क्या हासिल होगा? यानी कमाई और कथित रूप से सभ्य कहलाने की चिंता समूची सांस्कृतिक चेतना पर हावी है। ऐसे में उनकी मूल बोली किसी मानक भाषा के कारण मर रही है, इसको लेकर कोई खास मलाल नहीं है। भाव यही है कि अगर बोली से मातृभाषा और आंचलिक अस्मिता कायम रहने के अलावा कोई सुख नहीं मिल रहा तो इसे जिंदा रखने से क्या लाभ है?

लेकिन यह समस्या केवल हिंदी की बोलियों की ही नही हैं अन्य भारतीय भाषाओं की भी यही कहानी है, जिसमें मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तमिल भी शामिल है। खुद तमिल की 21 बोलियां हैं। जिसमे मध्य तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल को ही मानक भाषा माना जाता है। यह मानक भाषा ही पढ़ाई जाती है और साहित्य रचना भी मुख्य रूप से इसी भाषा में है। शासकीय व्यवहार की भाषा भी यही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बोली जानी वाली तमिल मद्रास बाशई (भाषाई) कहलाती है, जो तमिल के अलावा तेलुगू, कन्नड़, उर्दू, संस्कृत मलयालम आदि भाषाओं का मिश्रण है। इसकी तुलना बंबइया हिंदी से की जा सकती है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इसी भाषा का प्रयोग होता है। यही संपर्क भाषा भी है। खास बात यह है कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तमिल ब्राह्मण तमिल कहलाती है, जिसमें संस्कृत शब्द प्रचुर मात्रा में हैं। कहने कहने का आशय यह कि मानक तमिल भी तमिल बोलियों पर हावी हो रही है तो इसकी वजह व्यवहार में एकरूप तमिल की आवश्यकता है और जो कि स्वाभाविक है। इसी तरह अगर मानक हिंदी बोलियों का आंचल सिकोड़ रही है तो इसके पीछे उनका गला घोंटने की मंशा नहीं है, समय, सर्व सम्प्रेषणीयता और बढ़ते प्रादेशिक संपर्क की नैसर्गिक दरकार है।

यह बड़ा सवाल है कि मानक भाषाओं के दबाव के आगे बोलियां खुद को कैसे और किस रूप में बचाएं। इस सांस्कृतिक संपदा को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे उन्हें प्राचीन भाषा और मृत भाषा के तमगे के बचाएं। इसका उत्तर हमे अपने आप से पूछना होगा।

॥ मंदिरम् ॥

51

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इसे आमतौर पर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। मलयालम और तमिल में, 'तिरुवनंतपुरम' नाम का अर्थ है 'अनंत का शहर' (अनंत विष्णु का एक रूप है)। पद्मनाभस्वामी मंदिर की वास्तुकला केरल और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, जिसमें 100 फुट ऊंचा गोपुरम (अलंकृत प्रवेश द्वार) है। अंदर, मुख्य मंदिर में, प्रमुख देवता की 18 फुट ऊंची मूर्ति आदिशेष पर अनंतशयन मुद्रा में विराजमान है। पद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे महंगे मंदिरों में से एक है और भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसके छिपे हुए खजाने ने कभी-कभी लोगों की रुचि को आकर्षित किया है।

जीआईएस की सुमधुर स्मृतियां, दीर्घकालिक संबंधों का बनेंगी आधार

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में अतिथि देवो भव : के भाव को किया चरितार्थ
- समिट के लंच-डिनर सेशन ने देश-विदेश के प्रतिनिधियों को किया आकर्षित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पर्यटन व संस्कृति पर केंद्रित सत्र में कहा था कि मेले का मतलब है मेल-जोल बढ़ाना और ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट, उद्योगपतियों-निवेशकों-उद्यमियों और सरकार व प्रदेशवासियों के बीच मेल-जोल बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, यंग इन्नोवेटर, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की मंशानुसार निवेश के इस महाकुंभ में पधार रहे सभी अतिथियों का स्वागत-सत्कार, भारतीय संस्कृति के 'अतिथि देवो भवः' का भाव जीआईएस में साकार हुआ। उनका विचार था कि यह आयोजन परस्पर मेल-जोल, सद्भावना और सुखद अनुभूति के साथ हो और समिट की सुमधुर स्मृतियां, लंबे चलने वाले संबंधों का आधार बनें। अतः इस वैश्विक आयोजन में अतिथियों के आवागमन-आवास और भोजन की व्यवस्था के प्रति आरंभ से ही विशेष संवेदनशीलता रही। वैश्विक सम्मेलन में, विविधता से भरे हमारे देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ दुनिया के लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भोजन, सभी की मूल आवश्यकता है, परंतु अलग-अलग सामाजिक

-सांस्कृतिक-भौगोलिक परिवेश के कारण भोजन के लिए लोगों की आदतें, रुचियां और आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए इन विशिष्ट जन के लिए भोजन की व्यवस्था एक चुनौती थी। विविधता भरे समागम में सभी के स्वाद और संतुष्टि के अनुरूप भोजन की व्यवस्था करना, एक प्रकार से अपनी दक्षता का प्रमाण देने जैसा था। भोजन हमारी संपन्नता- सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह माना जाता है कि भोजन में लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। अच्छे स्वाद-सुगंध-स्पर्श और आकर्षक प्रस्तुतिकरण से भोजन की यह क्षमता और बढ़ जाती है। देश के दिल में बसे मध्यप्रदेश का भोजन, नए बदलावों को समरसता के साथ आत्मसात करने का प्रतीक है। स्वरुचि भोज परस्पर सौहार्द्र पैदा करने की सामर्थ्य रखते हैं। ग्लोबल समिट के लंच डिनर सेशन, प्रदेश की संपन्नता और आत्मीय तथा सर्व समावेशी व्यवहार के प्रकटीकरण का माध्यम बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए भोज देश-विदेश के उद्योग समूहों को मध्यप्रदेश के करीब लाने और उनमें राज्य के प्रति रुचि विकसित करने तथा परस्पर मेल-जोल बढ़ाने में सफल रहे। वैश्विक सम्मेलन में जापान से लेकर जर्मनी और अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका सहित लगभग सभी महाद्वीपों के देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से आए व्यापार-उद्योग जगत के प्रतिनिधि इस समागम को विविधता से परिपूर्ण बना रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लंच-डिनर सेशन में सबकी रुचि-संस्कृति-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता सब के स्वाद और स्वभाव अनुसार भोजन परोसा गया। खान-पान में मध्यप्रदेश और देश के प्रमुख व्यंजनों के साथ-साथ यूरोपियन, थाई, चाइनीस डिशेज शामिल थीं। जैन फूड, वीगन, मिलेट (श्री अन्न) और ग्लूटेन फ्री आहार लेने वालों का विशेष ध्यान रखा गया। भोजन तैयार करने में प्रदेश के प्रमुख शेफ, विशेषज्ञों, कारीगरों और इस क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं की मदद ली गई।

मध्यप्रदेश के व्यंजनों में हाउस ऑफ सैलाना के रॉयल क्यूज़ीन के अंतर्गत मोती के दाने, दाल बाफले, घुइयां की सब्जी, सिंघाड़े की चाट, मुरैना की गजक, झाबुआ का मालपुआ, उज्जैन की कुल्फी, हींग कचौड़ी, रिकमज की सब्जी, इंद्रहर, महुआ का मीठा, टेथरा की रबड़ी और भोपाली गोभी मुसल्लम खास रहे। देश के विभिन्न अंचलों के व्यंजनों में अमृतसरी छोले कुलचे, बिहारी लिट्टी चोखा, दक्षिण का डोसा-उत्तपम, मेरठ की रोटियां और पराठे, बंगाली चौम चौम और केसर अंगूरी रसमलाई परोसे गए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यंजनों में पास्ता, टॉर्ट, रिसोटो, ग्नौची, क्लासिक ओपेरा, बास्किन-रॉबिंस की आइसक्रीम, इंडो चाइनीस वोक, नूडल्स, थाय करी और डिम्सिम अतिथियों के आकर्षण का केंद्र रहे। मिलेट फूड के अंतर्गत कुटकी की खीर, रागी बालूशाही, मिलेट खिचड़ी, बाजरे की टिक्की तो जैन फूड में बिना प्याज, लहसुन के व्यंजन और मिलेट थालीपीठ शामिल थे।

भोपाल में 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड किया

- अकाउंट्स के एग्जाम में दो बार हो चुकी थी फेल, इसी से तनाव में थी

भोपाल। भोपाल के सेंट्रल स्कूल नंबर-1 में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह लगातार अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में फेल हो रही थी। इसे लेकर डिप्रेशन में थी। फायनल एग्जाम में भी उसे फेल होने की आशंका थी। परिजनों ने बताया कि इसी कारण युवती चिड़चिड़ी हो चुकी थी। मंगलवार को परिजन रोजा इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे थे। तभी लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। निशातपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पीपुल्स में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दोपहर में उसे सुपुर्देखाक किया जाएगा। एसआई हरीशंकर के मुताबिक नोशीन जाफरी पिता सबी हसन जाफरी (19) प्रीमीयम ऑर्चिड कॉलोनी करोंद 12 वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके पिता रेलवे में लोको पायलट हैं। मंगलवार शाम को परिवार के सभी लोग दो छोटी बहन और मां-पिता घर के ग्राउंड फ्लोर पर रोजा खोलने के इंतजार में थे। इफ्तारी करने के लिए नोशीन को छोटी बहन फर्स्ट फ्लोर पर स्थित रूम में बुलाने पहुंची थी। जहां कमरा अंदर से लॉक था। काफी आवाजें देने पर भी गेट नहीं खुला। तब मां पिता को आवाज देकर बुलाया। किसी तरह से पिता ने गेट खोलकर कमरे में प्रवेश किया, जहां बेटी का शव फंदे पर लटका था। शव उतारकर उसे पास के पीपुल्स अस्पातल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पिछले साल वह 12वीं क्लास का रिजल्ट बिगड़ने के बाद उसने क्लास रिपीट की थी। इस साल भी फर्स्ट टर्म से लेकर प्री बोर्ड तक उसका अकाउंट्स का एग्जाम बिगड़ता आ रहा था। इसी से वह तनाव में रहती थी। शुरुआती जांच में परिजनों ने सुसाइड का केवल यही कारण बताया है।

लाइनमैन दिवस पर तीन लाइनमैन हुए सम्मानित

नई दिल्ली में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का जलवा

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों पर उच्च प्रदर्शन करने वाले तीन लाइनमैन का सम्मान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में किया गया। सम्मानित होने वालों में कंपनी के जूनियर इंजीनियर श्री संतोष कुमार अहिरवार को नोडल अधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया है। साथ ही कंपनी कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हरदा वृत्त में कार्यरत वरिष्ठ लाईन अटेंडेंट श्री रामदीन सेजकर, ग्वालियर शहर वृत्त अंतर्गत कार्यरत श्री अशोक बुनकर एवं श्री अर्जुन बिनजावे को सम्मानित किया गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मान समारोह -2025 में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चार कार्मिकों को अवार्ड मिलने पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल

ने सभी कार्मिकों को बधाई दी है। गौरतलब है कि समारोह में देश की लगभग 70 डिस्कॉम, 28 ट्रांसमिशन कंपनियों तथा 25 जनरेशन कंपनियों ने भाग लिया। इसमें से मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के चार कार्मिकों को हाई परफार्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड मिला। कंपनी के कार्मिकों को यह अवॉर्ड हमेशा सुरक्षा किट प्रयोग किए जाने, निरन्तर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्य करने, तनाव रहित सेवा कार्य करते हुए सुरक्षा मानकों को बेहतरीन ढंग से अपनाने के लिये मिला है।

कलेक्टर को स्कूल के सामने मिला अतिक्रमण, बोले-तत्काल हटाओ

भोपाल के बैरसिया पहुंचे, सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग देखी, मंडी का निरीक्षण भी किया

भोपाल। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह बुधवार को बैरसिया क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग देखीं और कृषि उपज मंडी में भी निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम राइज स्कूल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साइट इंजीनियर को निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने एवं निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने को कहा। वहीं, एसडीएम आशुतोष शर्मा को निर्देश दिए कि स्कूल की बाउंड्रीवॉल और उसके गेट के सामने का अतिक्रमण हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान यह अतिक्रमण कलेक्टर ने दिखा था। कलेक्टर

ने कृषि उपज मंडी बैरसिया का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने ई-मंडी के कार्यों का स्वयं पोर्टल पर परीक्षण किया। उन्होंने आगामी उपार्जन कार्यों के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने तहसील बैरसिया में संपादित होने वाले राजस्व कार्यों का परीक्षण करते हुए एसडीएम बैरसिया को निर्देशित किया कि फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर एंट्री, सीएम हेल्पलाइन सहित सभी कार्यों में एक सप्ताह के भीतर उल्लेखनीय प्रगति का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने एसडीएम शर्मा से कहा कि बैरसिया की मुख्य सड़कों से एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही, एसडीएम एवं तहसील कार्यालय बैरसिया के साथ-साथ शहर की प्रमुख सड़कों को नगरीय निकाय के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त कर सौंदर्यीकरण किया जाए।

ऐशबाग थाने के टीआई और चार जवानों पर गिरी गाज

कॉल सेंटर पर छापेमारी में खामी के बाद लिया ऐक्शन

भोपाल। ऐशबाग थाने के टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई एक ठगी के कॉल सेंटर के संचालक पर एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण हुई है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने यह कदम उठाया है। यह कॉल सेंटर लोगों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर ठगता था। टीआई जितेंद्र गढ़वाल और एएसआई पवन रघुवंशी पहले भी विवादों में रहे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐशबाग थाने के टीआई जितेंद्र गढ़वाल, एएसआई पवन रघुवंशी और दो अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कॉल सेंटर के संचालक पर एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी के कारण हुई है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि टीआई जीतेंद्र गढ़वाल, एएसआई पवन रघुवंशी और दो अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पिछले दिनों कॉल सेंटर पर ऐशबाग पुलिस ने छापा मारा था। कार्रवाई में कई त्रुटियां थीं। इस मामले में मुख्य आरोपी अफजल खान को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। उससे तीन दिन की पुलिस रिमांड में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कार्रवाई में देरी के चलते तीन दिन पहले ही एएसआई पवन रघुवंशी को लाइन अटैच कर दिया गया था। टीआई जितेंद्र गढ़वाल और एएसआई पवन रघुवंशी पहले भी कई विवादों में रहे हैं। पिछले दिनों इन पर एनडीपीसी की फर्जी कार्रवाई करने के आरोप भी लगे थे। आरोप है कि जुए की बंदी न देने पर जुआरी फरहान खान पर एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले की शिकायत भी आला अधिकारियों तक पहुंची थी। ऐशबाग पुलिस ने 23 फरवरी को इस कॉल सेंटर पर छापा मारा था। इस दौरान अफजल के बेटे को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उस पर धारा 151 की कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो कॉल सेंटर संचालक अफजल और उसकी बेटी पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस जांच में पता चला है कि अफजल के खातों में देश भर में की गई ठगी के करीब एक करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। आरोपी के अपने नाम पर तीन खाते हैं। इसके अलावा, उसके रिश्तेदारों और कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर भी कई खाते हैं, जिनका इस्तेमाल वह साइबर ठगी के लिए करता था। शुरुआती जांच में 40 खातों की जानकारी सामने आई है। मास्टर माइंड अफजल ने इसमें अपने तीन खाते बताए हैं। बाकी खाते कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर खुलवाए गए थे। कॉल सेंटर में काम करने वाले 29 युवक-युवतियों के नाम भी सामने आए हैं।